श्रावण कृष्ण पक्ष-8, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 32 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
06 अगस्त 2026 गुरुवार

आज का मौसम
30.2 अधिकतम
24.3 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मध्यप्रदेश भू-विकास नियम 2012 को बना लिया आधार

रिहायशी बस्तियों में अवैध कारोबार की जांच सरकार खुद कराएगी या सुप्रीम कोर्ट?

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम का अभियान आज से फिर शुरू होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और आदेश के बाद पिछले सप्ताह जिन दुकानों, शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया था, उनमें से कई ने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया था। सवाल यह है कि वर्षों तक अवैध निर्माण और गतिविधियां जिन लोगों की मिलीभगत से चलती रहीं, उनकी जांच सरकार अपनी ओर से कराएगी या फिर इसके लिए भी सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का इंतजार करेगी।

दरअसल, प्रदेश के रहवासी क्षेत्रों में अवैध रूप से कमर्शियल गतिविधियां चलाने वाले लोग मध्यप्रदेश भू-विकास नियम 2012 का सहारा लेते रहे हैं। इसमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके नियम 12 में व्यावसायिक कार्यों की सूची दी गई है। इनमें सिलाई, रेडीमेड गारमेंट, कढ़ाई

फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग, चश्मा बनाना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, कंप्यूटर एवं लैपटॉप की असेंबली और रिपेयर, साइकिल रिपेयर ,मिठाई, पापड़, जैम, सॉस निर्माण, पुस्तक बाइंडिंग, डिटर्जेंट, अगरबत्ती, मोमबत्ती आदि का निर्माण, 7.5 KW तक की आटा चक्की, कंप्यूटर, सर्वर और डिजिटल स्टोरेज उपकरणों की असेंबली जैसी तकनीकी गतिविधियाँ शामिल हैं। लेकिन इसकी आड़ में बड़े शोरूम और शॉपिंग मॉल तक खुल गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भोपाल नगर निगम की कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षा के लिए गठित समिति की वजह से रुक गई थी लेकिन अब कोर्ट ने उसे भी भंग करते हुए राहत का आधार मानने से इनकार कर दिया हैं। ऐसे में सरकार और निगम के पास सख्त कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि मास्टर प्लान और नगर नियोजन के नियमों का पालन अनिवार्य है तथा किसी भी अवैध उपयोग को नियमित करने का अधिकार नियमों के विपरीत नहीं हो सकता।

अरेरा कॉलोनी के सभी हिस्सों में इस तरह के बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए हैं।

सीलिंग, जुर्माना और बिजली काटने का भी प्रस्ताव

शहर में लंबे समय से आवासीय मकानों में शोरूम, क्लीनिक, कोचिंग सेंटर, बैंक्वेट कार्यालय, गोदाम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। इससे पार्किंग, यातायात, अग्नि सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। निगम अधिकारियों के अनुसार अभियान चरणबद्ध तरीके से चलेगा और प्रत्येक जोन में सूचीबद्ध परिसरों का सत्यापन कर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग, जुर्माना और बिजली तथा अन्य सुविधाओं को बंद कराने जैसी कार्रवाई भी प्रस्तावित है।जिन मामलों में नियमों के अनुसार सीमित व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है, उन्हें अलग रखा जाएगा, जबकि पूरी तरह अवैध उपयोग वाले मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।

अरेरा कॉलोनी में एक रुपए की जमीन से करोड़ों के कारोबार तक...

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का अरेरा कॉलोनी क्षेत्र आज केवल एक पॉश आवासीय इलाका नहीं, बल्कि शहरी नियोजन, भू-विकास नियमों और प्रशासनिक जवाबदेही पर खड़े अनेक सवालों का प्रतीक बन चुका है। जिस कॉलोनी की परिकल्पना विशुद्ध रूप से आवासीय उपयोग के लिए की गई थी, वहां आज बड़े-बड़े शोरूम, निजी अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। प्रश्न यह है कि यह सब किन नियमों के तहत हुआ?

प्रसंगवश
राजेश सिरोठिया

मध्यप्रदेश में वर्तमान में लागू भू-विकास नियम, 2012 तथा उससे पहले के मास्टर प्लानों का मूल उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों के स्वरूप और गुणवत्ता को सुरक्षित रखना था। नियम 37 तथा उसके अंतर्गत श्वश्वद्गठ्ठस्रद्ब×-स्न स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आवासीय क्षेत्रों में केवल सीमित और निर्दिष्ट घरेलू, सेवा आधारित तथा लघु गतिविधियों की ही अनुमति है। इसके बावजूद भोपाल के अनेक आवासीय क्षेत्रों, विशेषकर अरेरा कॉलोनी में, वर्षों से ऐसे व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग विकसित होते गए जो प्रथम दृष्टया इन नियमों की भावना से मेल नहीं खाते। अरेरा कॉलोनी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वर्ष 1970 के दशक में इस क्षेत्र के 2,400 से लेकर 10,000 वर्गफुट तक के विशाल भूखंड वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मात्र एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर से आवंटित किए गए थे। उद्देश्य था कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक उच्च स्तरीय, शांत और विशुद्ध आवासीय कॉलोनी विकसित की जाए।

समय बदला। कई अधिकारियों के परिवार अन्य शहरों या विदेशों में बस गए। बड़े-बड़े बंगले ऊँची कीमतों पर नए खरीदारों–ज्वेलर्स, बिल्डर्स और अन्य संपन्न कारोबारी परिवारों–को बेच दिए गए। इसके बाद अनेक परिसरों का उपयोग केवल आवास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनते चले गए। अरेरा कॉलोनी के मूल स्वरूप को बनाए रखने के सबसे बड़े पक्षधर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं पद्मश्री महेश नीलकंठ बुच थे। उनका स्पष्ट मत था कि इस क्षेत्र का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए होना चाहिए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में कई प्रस्तावित व्यावसायिक निर्माणों का विरोध किया। लेकिन उनके निधन के बाद कॉलोनी का स्वरूप तेजी से बदलता गया।

आज राजीव गांधी चौराहे और उसके आसपास का क्षेत्र इस बदलाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ बड़े शोरूम, निजी अस्पताल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। यदि इन संस्थानों को भूमि उपयोग परिवर्तन या अन्य वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त हैं, तो उनका सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। यदि नहीं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वर्षों तक नियामक एजेंसियाँ मौन क्यों रहीं? यही वह बिंदु है जहाँ यह केवल अरेरा कॉलोनी का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि पूरे प्रदेश में भू-विकास नियमों के समान अनुपालन और प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है।

न्यूज विंडो

केजरीवाल का दावा- इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित किया गया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने 'एक्स' पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए बताया कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इसके पीछे की वजह भी नहीं बताई गई और मेटा की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

बांग्लादेश में क्रिकेटर शाकिब के घर पर हमला, पेट्रोल बम फेंके

ढाका। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के मगुरा शहर में बने घर पर हमला हुआ है। यह घटना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब के शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई। शाकिब के घर पर हमला रात 8.45 से 9 बजे के बीच हुआ। मगुरा सदर पुलिस के अफसर मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और खिड़कियां तोड़ दीं।

पोलार्ड का रिकॉर्ड टूटा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने बटलर

मैनचेस्टर । इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने जारी द हंड्रेड लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स बनाम वेल्श फायर मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वेल्श फायर के खिलाफ बटलर ने 51 रनों की पारी खेली। इसी के साथ वह टी20 के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है।

आज का कार्टून

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

तहलका के तेजपाल रेप केस में दोषी करार

मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने आज तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है। उन्हें आज ही सजा सुनाई जाएगी। तेजपाल को मई 2021 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।

जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच ने तीन दिन की अंतिम सुनवाई के बाद 30 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, तहलका की महिला पत्रकार ने 2013 में तेजपाल पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था।

पीड़ित के मुताबिक तेजपाल ने 7-8 नवंबर 2013 को गोवा में थिंकफेस्ट इवेंट के दौरान होटल की लिफ्ट में उनका उत्पीड़न किया था।

ईरान की धमकी: अटैक किया तो एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाएंगे

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान। ईरान ने गल्फ देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊर्जा ढांचे पर फिर हमला किया, तो वह पूरे इलाके के तेल ठिकानों, रिफाइनरियों, बिजली ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्किये और पाक के शीर्ष नेताओं से बात कर अमेरिका पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि नया हमला टाला जा सके। ईरान का कहना है कि वह अभी भी कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा। इसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रम्प से बात कर सैन्य कार्रवाई टालने और बातचीत जारी रखने की अपील की।

रिजिजू-खड़गे में हुई बहस: कांग्रेस अध्यक्ष बोले- बोलना मेरा अधिकार

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी है। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा- अब मुझे रिजिजू से बोलना सीखना पड़ रहा है। वे चेयरमैन के चेंबर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहां आकर बोलता हूं।

खड़गे ने कहा- यहां बोलना मेरा अधिकार है। क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या बोलना है, ये तय करना मेरा अधिकार है।

इधर, लोकसभा कार्यवाही शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि विपक्ष का आचरण सही नहीं है। देश सरकार का जवाब सुनना चाहता है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा।

49 जिलों में बारिश औसत से कम, मजबूत सिस्टम से भरपाई की उम्मीद

मानसून की रफ्तार धीमी, प्रदेश के अधिकांश जिलों में सूखे जैसे हालात

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश में इस मानसूनी सीजन अब तक 16.3 इंच बारिश हुई है, जो औसत से 18% कम है। इस वजह से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत 49 जिलों की स्थिति ठीक नहीं है। सिर्फ 6 जिले ही बेहतर स्थिति में हैं। 5 बड़े शहरों की बात करें तो सिर्फ ग्वालियर में ही औसत से 7% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि भोपाल में औसत से 7%, इंदौर में 2%, उज्जैन में 14% और जबलपुर में 29% कम बारिश हुई है।

भोपाल, जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों में बारिश का आंकड़ा माइनस में है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल के 6 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है।

3 दिन तेज बारिश, उत्तरी हिस्सा ज्यादा भीगेगा

मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यदि सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा और तेज बारिश का दौर लगातार चला तो बारिश के आंकड़े में सुधार आने की उम्मीद है। गुरुवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह में भारी बारिश का अलर्ट है।

पानी की कमी से सूखे खेतों का हाल।

यूपी के 40 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसा

बद्रीनाथ हाई-वे बंद, मकान ढहने से 6 की मौत

देहरादून, लखनऊ। देश के कई हिस्सों मेंमानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। यूपी में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद जिले के 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया है। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का पानी 40-50 छोटे मंदिरों में घुस गया है। वहीं, प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के कारण 100 साल पुराना मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा के पास पहाड़ से मलबा और पानी केदारनाथ हाईवे पर आ गया। इससे कई गाड़ियां कीचड़ और चट्टानों के मलबे में दब गईं। चमोली में हेलंग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है।

मेट्रो एंकर | **नाबालिग की उम्र बदलकर किया था अबॉर्शन, अभिभावकों की सहमति भी नहीं ली गई**

गर्भपात का 'लाइसेंस' नहीं है MTP एक्ट, डॉक्टर पर मुकदमा चलेगा- हाईकोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट मांग करने पर गर्भपात करने का 'बिना शर्त लाइसेंस' नहीं है। यह कानून केवल तय शर्तों के तहत आपराधिक जिम्मेदारी से सीमित छूट देता है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने एक नाबालिग का गर्भपात कराने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने डॉ. पूनम मिश्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर सबूतों की गहराई से जांच नहीं की जा सकती।

मामला 16 साल की एक नाबालिग लड़की का गर्भपात कराने से जुड़ा है। आरोप है कि लड़की ने अस्पताल के रिकॉर्ड में अपनी सही जन्मतिथि दर्ज की थी, लेकिन डॉक्टर ने कथित तौर पर स्टाफ से उसकी उम्र 20 साल दर्ज करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यदि यह आरोप ट्रायल में सही साबित होता है, तो इसे जानबूझकर किया गया कृत्य माना जाएगा और डॉक्टर को कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मरीज की उम्र की पुष्टि करना डॉक्टर की बुनियादी जिम्मेदारी है। यदि मरीज नाबालिग है, तो केवल उसके साइन से गर्भपात नहीं कराया जा सकता। कानून के अनुसार अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य है। इसके बिना दी गई सहमति की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल या क्लिनिक की प्रशासनिक लापरवाही का हवाला देकर डॉक्टर अपनी व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया।

मामला यौन अपराध के दायरे में

हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट का भी जिक्र किया और कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के गर्भवती होने का मामला स्वतः यौन अपराध के दायरे में आता है। ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को देना रजिस्टर्ड डॉक्टर की कानूनी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि घटना की रिपोर्ट करने में 70 दिन की देरी को मामूली चूक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे पीड़िता की सुरक्षा और सबूत दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

घुटने में था दर्द, ठग बोला-विषैला तत्व निकालूंगा, हर बूंद के लूंगा 7 हजार रुपए

फर्जी फिजियोथैरेपिस्ट ने इलाज के नाम पर बुजुर्ग प्रोफेसर से ठगे 4 लाख रुपए

भोपाल. दोपहर मेट्रो

फिजियोथैरेपिस्ट बनकर ठगों ने सीहोर कृषि कॉलेज के प्रोफेसर को चार लाख रुपए का चूना लगा दिया। घुटने में घुटने के दर्द से परेशान प्रोफेसर को शातिर ने ऐसे ठगा कि प्रोफेसर रुपए देने को विवश हो गए। समय रहते ठगी का अहसास होने पर प्रोफेसर ने बाकी के 6 लाख रुपए बचा लिए। कोहेफिजा पुलिस ने प्रोफेसर की शिकायत पर फर्जी फिजियोथैरेपिस्ट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

दरअसल, लोटस सुप्रीम सनसिटी एयरपोर्ट रोड निवासी प्रो. दीपरत्न सक्सेना (64) के घुटने में दर्द था। उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। कुछ दिन पहले उन्हें सब्जी मंडी में एक लड़के ने देखा और कहा, मेरे पिताजी को यही समस्या थी। अब पिताजी ठीक हो गए हैं। लड़के ने एक मोबाइल नंबर दिया और इस पर बात करने को कहा। प्रो. सक्सेना ने 29 जुलाई को फोन लगाया तो ट्रू कॉलर पर उसका नाम आशीष आचार्या शो होने लगा। बातचीत में उसने खुद को दिल्ली का फिजियोथैरेपिस्ट बताया। प्रोफेसर ने उसे अपनी बीमारी बताई। फर्जी फिजियोथैरेपिस्ट ने शत-प्रतिशत इलाज करने का दावा किया। इसके बाद आचार्या प्रोफेसर के घर पहुंचा। पहले कुशल डॉक्टर की तरह उसने प्रोफेसर के घुटने की जांच की। इसके बाद बोला-इलाज थोड़ा महंगा है, लेकिन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। घुटने में विषैला तत्व जमा हो गया है। इसे निकालना पड़ेगा।

इन्हें भी लूटा

कटारा हिल्स के निवासी अनिल विश्वकर्मा भी ठगी के शिकार हुए थे। बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर निर्माण यूनिट चलाने वाले अनिल से ठगों से सेना के अधिकारी बनकर बात की। 10 झूले खरीदने के लिए 2.08 लाख रुपए का ऑर्डर दिया। जब झूले तैयार हो गए तो भुगतान के नाम पर उसके खाते में 5 रुपए भेजे। ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के नाम पर अनिल को 10 रुपए भेजने को कहा। जैसे ही अनिल ने रुपए भेजे, खाते से 1 लाख रुपए पार हो गए।

..और शुरू हुआ ठगी का खेल

पुलिस ने बताया, प्रोफेसर के घर जाकर आशीष थैरेपी के नाम पर उनके घुटने पर ब्लेड से छोटा चीरा लगाया। आचार्या ने कहा, यह विषैला तत्व है। इसे निकालना होगा। एक बूंद तरल निकालने के लिए उसने 7 हजार रुपए मांगे। कुल खर्च 10 लाख रुपए बताया।

चार लाख नकद ले लिए और 6 लाख का चेक भी लिया

फर्जी फिजियोथैरेपिस्ट आचार्य ने इलाज के लिए चार लाख रुपए नकद ले लिए। बाकी 6 लाख रुपए का चेक भी ले लिया। रुपए लेने के बाद वह चंपत हो गया। इसी बीच प्रोफेसर दीपरत्न ने समाचार पत्र में खबर पढ़ी कि फिजियोथैरेपिस्ट गिरोह बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। वह दर्द से छुटकारा दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठता है और गायब हो जाता है। इसके बाद बुजुर्ग को ठगी का अहसास हुआ। प्रोफेसर ने तुरंत 6 लाख रुपए का चेक स्टॉप कराया।

ऐसे बचें

- **किसी अनजान व्यक्ति से मिलें तो तुरंत घरवालों को बताएं**
- **किसी से भी बैंक खाते की जानकारी साझा न करें**
- **मोबाइल पर आने वाले तमाम तरह के ऑफर्स को ना कहें**
- **फोन पर किसी तरह का दबाव में न आएं। तुरंत फोन काट दें**
- **ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करें**

सावधान! इन हथकंडों से भी हो रही है ठगी

1. माशिमं के रिटायर्ड अफसर से ठगी: माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के रिटायर्ड अफसर अनिल कुमार झारिया के बैंक खाते में भी साइबर ठगों ने सेंध लगा दी। उनके खाते से तीन बार में 99 हजार रुपए उड़ा लिए। हबीबगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2. इंजीनियर भी ठगाए: क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वॉइंट रिडीम कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने साफ्टवेयर इंजीनियर भूपेश रैकवार (25) से 4.20 लाख रुपए ठग लिए। सेकंड स्टॉप तुलसी नगर निवासी इंजीनियर को ठगों ने बैंकर बनकर फोन किया। मुफ्त रिवार्ड लेने की योजना बताई और फायदा लेने का अंतिम दिन भी बताया। सेकंड स्टॉप, तुलसी नगर में रहने वाले भूपेश रैकवार एक निजी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर हैं।

शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खस्ताहाल

दरक रहीं दीवारें, रिस रही छत, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर

भोपाल. दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की इमारत जर्जर होती जा रही है। कई दीवारों में दरारें आ गईं तो जगह-जगह से प्लास्टर गिरने लगा है। बरसात में भवन की हालत और खराब हो गई है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों-कर्मचारियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कॉलेज में रोजाना पढ़ने आने वाले सैकड़ों विद्यार्थी जर्जर भवन के कारण भय के माहौल में पढ़ाई को मजबूर हैं। छात्रों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि भवन की तत्काल जांच कराकर मरम्मत कार्य शुरू कराया जाए। ऐसा न होने पर वैकल्पिक तौर पर विद्यार्थियों को दूसरे भवन में पढ़ाने की व्यवस्था करें।

दरक रही है छत

कई स्थानों पर छत से सीलन और पानी टपकने की शिकायत भी सामने आ रही है। छात्रों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं कराया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यार्थियों का आरोप है कि कई बार अफसरों को बताया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एमपीआरडीसी ने डीपीआर के लिए जारी किए टेंडर

भोपाल-ग्वालियर के बीच बनेगा 320 किलोमीटर लंबा फोरलेन

भोपाल. दोपहर मेट्रो। भोपाल से ग्वालियर के बीच करीब 320 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल फोरलेन कॉरिडोर को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए टेंडर जारी किया है। डीपीआर के दौरान तीन संभावित अलाइनमेंट का सर्वे कर अंतिम रूट तय किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, बायपास, इंटरचेंज और अन्य तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर परियोजना का अंतिम स्वरूप तैयार होगा। यह हाईवे 6.23 करोड़ से बनेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि प्रस्तावित फोरलेन किन शहरों और गांवों से होकर गुजरेगा। फिजिबिलिटी के आधार पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। यानी, सड़क नए मार्ग पर बनेगी। इसमें प्रवेश एवं निकास केवल निर्धारित इंटरचेंजों से ही होगा। एमपीआरडीसी ने डीपीआर के लिए शर्त रखी है कि कंसल्टेंट विकल्पों का सर्वे कर उपयुक्त अलाइनमेंट का चयन करे।

भोपाल-ग्वालियर की दूरी 100 किमी हो जाएगी कम

अभी ग्वालियर से भोपाल जाने के लिए शिवपुरी-गुना होकर जाना पड़ता है। यह दूरी 428 किमी है। इसे तय करने में साढ़े सात घंटे लगते हैं। नए रूट तलाशने से दूरी 320 किमी हो जाएगी।

झीलों की नगरी में सांस्कृतिक समागम

भोपाल. दोपहर मेट्रो। ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए राजधानी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक चल रही है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें क्रिएटिव इकोनॉमी, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास जैसे प्रमुख विषयों पर विचार साझा किए। इसमें लगी प्रदर्शनी को देखने भी राजधानीवासी उमड़ रहे हैं।

हरियाली महोत्सव, आकर्षण का केंद्र सावन सुंदरी प्रतियोगिता

भोपाल. दोपहर मेट्रो। कायस्थ मंडल नगरीय क्षेत्र वेलफेयर सोसाइटी, होशंगाबाद रोड द्वारा 22 अगस्त को शाम 5 बजे नंदन पैलेस में हरियाली महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सावन सुंदरी प्रतियोगिता, सावन पर आधारित नृत्य-गीत और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला और युवती प्रतिभागियों को विजेता एवं उपविजेता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। मंडल की ओर से इच्छुक महिलाओं और युवतियों से प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने नाम श्रीमती साधना श्रीवास्तव, श्रीमती अनु श्रीवास्तव, श्रीमती नीना सक्सेना और श्रीमती मंजूषा श्रीवास्तव के पास दर्ज कराने का आग्रह किया गया है।

हरे कपड़ों में आएंगे

आयोजन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हरे रंग के वस्त्र पहनना अनिवार्य रहेगा। कार्यक्रम के समापन के बाद सहभोज का भी आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मंडल के प्रवक्ता अभय प्रधान ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

कजलीखेड़ा: पत्नी के मायके जाने से दुखी पति ने घर में ही लगाई फांसी

भोपाल. दोपहर मेट्रो। कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि मोहल्ला में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्राथमिक जांच में पता चला कि उसकी शादी 10 माह पहले ही हुई थी। एक सप्ताह पहले पत्नी गोंडीपुरा मायके चली गई। इससे वह दुखी था। पुलिस ने बताया कि गोलू नदानिया पिता श्रीलाल (24) सफाईकर्मी था। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात उसने अपने कमरे में पाइप पर दुपट्टे से फंदा लगा लिया।

पड़ोसन ने रंजिश के चलते 9 साल की बच्ची को पालतू कुत्ते से कटवाया, केस

भोपाल. दोपहर मेट्रो

राजधानी के गांधी नगर थाना क्षेत्र में पड़ोसन ने पुरानी रंजिश में 9 साल की मासूम बच्ची पर जानबूझकर पालतू कुत्ते को उकसाकर कटवा दिया। बच्ची घायल है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ लापरवाही से जानवर पालने और दूसरों की जान खतरे में डालने की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, टैगोर वार्ड निवासी कृष्णकांत रावत ने शिकायत में बताया कि 3 अगस्त की शाम बेटी घर के बाहर साइकिल चला रही थी। तभी पड़ोसी रामू की पत्नी संजना दो पालतू कुत्तों के साथ बाहर खड़ी थी। पुरानी रंजिश के कारण दोनों परिवारों के बीच आपसी बातचीत बंद थी। कृष्णकांत का आरोप है कि जैसे ही बच्ची साइकिल से कुत्तों के पास से गुजरी, संजना ने बेटी पर कुत्ते छोड़ दिए। दोनों कुत्ते अचानक मासूम बच्ची पर झपट पड़े और उसके पैरों में कई जगह काट लिया।

बच्ची की चीख-सुनकर पहुंचे। तुरंत डंडे से कुत्तों को भगाया और बेटी को केयरवेल अस्पताल ले गए। यहां उनका इलाज किया गया।

एनालॉग पनीर दे सकता है दिल का दर्द, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अपने यहां भी बैन लगाने की तैयारी

पड़ोसी राज्यों के फैसलों का परीक्षण कराएगा खाद्य विभाग, देखेगा रिपोर्ट, फिर निर्णय

भोपाल. दोपहर मेट्रो

पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब मप्र में भी इन राज्यों के प्रतिबंध लगाने के कारणों का परीक्षण होगा। प्रदेश में अब तक लिए सैंपलों की रिपोर्ट देखी जाएगी। अमानक सैंपल का आकलन होगा। इसी आधार पर प्रदेश में भी इस पर निर्णय संभव है। बता दें, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण डेयरी उत्पादों के तहत एनालॉग पनीर बनाने अनुमति दी है।

जिन राज्यों में एनालॉग पनीर पर रोक लगी है, वहां के निर्णयों का परीक्षण कराएंगे। इसका कारण देखेंगे। इसी आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
- मनोज पुष्प, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मिलावट पहले भी पकड़ी गई है

मिलावट और उपभोक्ताओं से कई होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और क्लाउड किचन में धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। जांच में सामने आया था कि एनालॉग पनीर को वे असली पनीर बताकर उपभोक्ताओं को परोस रहे थे।

क्या है पनीर और एनालॉग पनीर

पनीर: दूध से बना डेयरी उत्पाद। मुख्य कच्चा माल दूध या मिल्क सॉलिड होते हैं। वसा का स्रोत सिर्फ मिल्क फैट है।
एनालॉग पनीर: गैर दुग्ध चीजों से बनाते हैं। वनस्पति वसा, वनस्पति प्रोटीन, स्टार्च का उपयोग होता है।

क्यों खतरनाक

- इसमें मौजूद हाइड्रोजनेटेड फैट और ट्रांस-फैट के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दिल से जुड़ीं बीमारियां हो सकती हैं।
- शरीर में सूजन जैसी दिक्कत संभव है।

मेट्रो एंकर कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का समापन

प्रेमचंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक: मैथिल

भोपाल. दोपहर मेट्रो

'क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे...वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते-घटते लुप्त हो जाता है' ये विचार आम आदमी को शब्दों में पिराने वाले कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के हैं। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने बरसों पहले थे। ये बातें वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम मैथिल अमृत ने कहीं। वे कथा सम्राट प्रेमचंद की 146वीं जयंती के मौके पर क्षेत्रीय वेल्डिंग प्रशिक्षण संस्थान सभागार, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा, प्रेमचंद की रचनाएं समाज को दिशा देती हैं। युवा पीढ़ी को उनके साहित्य से जरूर जुड़ना चाहिए। उनके अलावा कई साहित्यकारों ने भी अपनी बात रखी।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में बाल भारती पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक और पुस्तक प्रेमी भी प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने साहित्य से जुड़े प्रश्न पूछे और सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें भी खिंचवाईं। कार्यक्रम में वरिष्ठ अनुवादक एवं संयोजक राकेश कुमार मालवीय, अनिल साकेत, रामगोपाल मंगल, गुलाब सिंह सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे।

मुंशी
प्रेमचंद की तस्वीर के साथ सेल्फी लेतीं छात्राएं।

कलम से रच देते थे पूरे समाज की छवि

प्रदर्शनी में मुंशी प्रेमचंद की 100 से भी अधिक महत्वपूर्ण कृतियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। उनकी लिखी पुस्तक गोदान, गबन, कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और पूस की एक रात जैसी कालजयी रचनाओं के साथ उनके पात्रों और प्रसंगों को मूर्तियों, चित्रों तथा अन्य सामग्री के माध्यम से सजीव रूप दिया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले सभी आगंतुकों ने राजभाषा अनुभाग के इस अभिनव प्रयास की प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने मुंशी प्रेमचंद की किताब के कुछ पन्ने ही पलटाए तो पढ़ते चले गए। कभी पूस की रात में हल्कू का दृश्य आंखों के सामने नाचने लगा तो कभी 'नमक का दारोगा' का किरदार जीवंत हो गया। उन्होंने कहा, मुंशी प्रेमचंद समाज का आईना थे।

कोलार फिल्टर प्लांट से जारी रहेगी पानी की सप्लाई 70 इलाकों को बड़ी राहत

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजधानी के 70 से ज्यादा इलाकों को बड़ी बड़ी राहत मिली है। बिजली की कटौती में भी कोलार फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई जारी रहेगी। बिजली मेंटेनेंस या खराबी के कारण अब रहवासी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। इसके लिए 132 केवी महाबड़िया एक्स्ट्रा हाईटेंशन सब स्टेशन पर 50 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी है। इससे कोलार प्लांट को स्थायी रूप से वैकल्पिक बिजली स्रोत मिलता रहेगा।

10 करोड़ की डिपॉजिट स्कीम

मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश शांडिल्य के अनुसार, महाबड़िया सब स्टेशन पर लोड 80 फीसदी से कम है। भविष्य में मेंटेनेंस का असर जलापूर्ति पर न पड़े, इसके लिए नगर निगम डिपॉजिट स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपए देगा। इससे यह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। बता दें, 10 दिन पहले बिजली शटडाउन से कोलार फिल्टर प्लांट बंद हो गया था।

प्रदेश के पहले मेंटल हेल्थ सेंटर का काम अटका

फंड की कमी, 22 करोड़ का प्रोजेक्ट चार साल में भी पूरा नहीं हो सका

इंदौर/भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। बाणगंगा स्थित मानसिक चिकित्सालय में 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी यह अधूरा पड़ा है। अंतिम चरण में पहुंचे इसके निर्माण कार्य पर रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्वीकृति, लगभग 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट और फंड की कमी के कारण एक बार फिर ब्रेक लग चुका है। इससे पूर्व भी भुगतान और फंड की कमी के चलते यह प्रोजेक्ट 3 बार ठप हो चुका है।

इस प्रोजेक्ट के टेंडर पीडब्ल्यूडी की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पीआईयू) के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसकी कुल लागत 22 करोड़ 23 लाख रुपए तय हुई थी। भोपाल की एक एजेंसी ने 23 प्रतिशत कम दर पर लगभग 17.5 करोड़ रुपए में इसका ठेका लिया था। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने की समय-सीमा तय की गई थी, परंतु फंड जारी होने में लगातार हो रही देरी के कारण 48 महीने बीत जाने पर भी काम पूरा नहीं हो सका है। शुरुआत में बिजली की एलटी लाइन शिफ्ट करने में हुई देरी से 3-4 महीने काम रुका रहा। इसके उपरांत भुगतान में देरी के चलते 2 बार लंबे समय तक निर्माण बंद रहा, जिसके संबंध में पीआईयू अधिकारियों ने लगातार पत्राचार किया। एजेंसी को बकाया राशि का भुगतान होने के उपरांत कुछ महीने पहले ही कार्य पुनः प्रारंभ हुआ था।

अतिरिक्त फंड और रिवाइज्ड एस्टीमेट का पेच| अतिरिक्त निर्माण और अन्य कारणों से प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट और रिवाइज्ड एस्टीमेट की मंजूरी के लिए पीआईयू द्वारा प्रस्ताव आगे भेजा गया है। इसकी स्वीकृति के इंतजार में पिछले 1 महीने से काम फिर से बंद पड़ा है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों का लगभग 1.5 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान भी अभी अटका हुआ है। इस विषय पर पीडब्ल्यूडी (की एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती यादव ने बताया कि प्रक्रिया जारी है, जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा।

हम कई पत्र लिख चुके

शासकीय मनोचिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. वीएस पाल के अनुसार, लंबे समय से निर्माण पूरा होने की प्रतीक्षा की जा रही है, परंतु काम अभी तक अधूरा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से निर्माण एजेंसी को लगातार कई पत्र लिखे जा चुके हैं, फिर भी कार्य बंद है। यदि भवन समय पर हैंडओवर हो जाए, तो उपकरणों और फर्नीचर की खरीद प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिसके लिए बजट पहले से स्वीकृत है। इसके अलावा आवश्यक फैकल्टी और स्टाफ पदों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह परियोजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना (एनएमएचपी) के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी। इस सेंटर के बनने से नशा मुक्ति केंद्र के साथ-साथ मनोरोगों के उपचार हेतु विभिन्न विशिष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह संस्थान एक रिसर्च सेंटर के रूप में नए शोधों को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा, जो प्रदेश का अपनी तरह का पहला विशेषज्ञ स्तर का मानसिक स्वास्थ्य केंद्र साबित होगा।

सीएम मोहन ने शिक्षकों-छात्राओं को दिया सफलता का मंत्र, बोले-

सपने बड़े देखो, मेहनत जी-तोड़ करो, आज का विद्यार्थी ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के टी.टी. नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनि शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि ÷मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी हैं। आज इन युवाओं के चेहरों पर मुझे विकसित भारत का उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है।÷ मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का विद्यार्थी ही कल का भारत है और राज्य सरकार हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश इस समय अमृतकाल से गुजर रहा है और आज की युवा पीढ़ी ही भारत के भविष्य की निर्माता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और नवाचार से ही पूरा होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उनके पास बड़े सपने हैं तो सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य तय कर पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में इतनी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन आज सांदीपनि विद्यालय आधुनिक शिक्षा और बेहतर संसाधनों के कारण नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था और गुरु-शिष्य परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि भारत केवल आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि संस्कारों, जीवन मूल्यों और ज्ञान के बल पर विश्व में सम्मान प्राप्त करता है।

विद्यार्थियों के सपने साकार करेगी मध्यप्रदेश सरकार

कृषि से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर और सेना में अधिकारी बनने के साथ-साथ कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा ही प्रदेश और देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। राज्य सरकार युवाओं और किसानों के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है।

नई शिक्षा व्यवस्था और सांदीपनि विद्यालयों का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहले चरण में 274 सांदीपनि विद्यालय तथा जनजातीय कार्य विभाग के 94 विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। दूसरे चरण में 200 नए सांदीपनि विद्यालय और जनजातीय विभाग के 205 नए विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाया जा रहा है।

विद्यार्थियों को दिलवाया विकसित मध्यप्रदेश का संकल्प

विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों चंद्रशेखर आजाद, सुभाषचंद्र बोस, बालगंगाधर तिलक, भगत सिंह और महात्मा गांधी के त्याग और उनके सपनों का उल्लेख कर विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहाँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसे पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी युवा एवं विद्यार्थियों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आप में से अधिकांश युवा होंगे।

एआई का उपयोग करें, लेकिन अपनी सोच भी रखें

संवाद के दौरान छात्राओं ने मुख्यमंत्री से कई रोचक सवाल पूछे। एक छात्रा ने पूछा कि क्या वह चैट-जीपीटी का उपयोग करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कार्यक्रमों और समसामयिक विषयों की जानकारी जुटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि एआई का उपयोग करें, लेकिन अपनी समझ और विवेक भी जरूर लगाएं तथा तथ्यों की जांच अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वह सामाजिक माध्यमों का उपयोग करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुसरण करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, खेलकूद, समय प्रबंधन, डायरी लेखन और निरंतर सीखने की आदत अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि जीवन में पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती, सीखने की जिज्ञासा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है।

मध्य प्रदेश में बच्चों पर बढ़ा खतरा!

हर छह में से एक अपहरण का मामला प्रदेश से, गृह मंत्रालय के आंकड़ों ने बढ़ाई बड़ी चिंता

पांच साल में 64 फीसदी बढ़े बाल अपहरण के मामले, देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा मप्र

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में बच्चों के अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में 11,594 बाल अपहरण और व्यपहरण के मामले दर्ज किए गए। यह देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे अधिक 12,950 मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इसके बाद हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में बाल अपहरण के 7,058 मामले दर्ज हुए थे। यानी पांच वर्षों में इन मामलों में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देशभर में वर्ष 2024 के दौरान बच्चों के अपहरण के 75,108 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से अधिक रही। इसका मतलब है कि देश में दर्ज होने वाला लगभग हर छठा मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है।

हालांकि रिपोर्ट का दूसरा पक्ष कुछ राहत देने वाला है। वर्ष 2024 में प्रदेश में 11,669 बाल पीड़ित दर्ज किए गए, जबकि 11,652 बच्चों को जीवित बरामद कर लिया गया। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बरामदगी के आंकड़ों में पिछले वर्षों में अपहृत होकर बाद में मिले बच्चों को भी शामिल किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि पुलिस और बचाव एजेंसियों की कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। बच्चों की तलाश और बचाव के लिए केंद्र सरकार ने कई तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को मिशन वात्सल्य से जोड़ा गया है।

हाल के मामलों ने बढ़ाई चिंता

हाल के दिनों में सामने आए मामलों ने भी प्रदेश में बाल सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इंदौर में बाणगंगा पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया, जो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उन्हें बालिग बताकर जबरन शादी कराता और लाखों रुपये की ठगी करता था। वहीं ग्वालियर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस से अगवा 18 माह की बच्ची को जीआरपी ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते आंकड़े यह साफ संकेत दे रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, सतर्कता और परिवारों की भागीदारी भी इस गंभीर समस्या पर रोक लगाने के लिए बेहद जरूरी है।

प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों का अकाल

दो दर्जन संचालनालय में कर रहे अफसरी ,स्त्री और शिशु रोग विशेषज्ञों की भी कमी

भोपाल। दोपहर मेट्रो

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आधे से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, जबकि कई विशेषज्ञ वर्षों से स्वास्थ्य संचालनालय और एनएचएम में प्रशासनिक काम कर रहे हैं। इससे जिला अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी के बीच स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। एक ओर प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 4,573 स्वीकृत पदों में से 2,581 पद (56.44त्न) खाली हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संचालनालय (डीएचएस) में 24 विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थ हैं। इनमें तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ ऐसे हैं, जो पिछले 25 वर्षों से संचालनालय में ही पदस्थ हैं। प्रदेश के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, सर्जन, फिजिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण कई अस्पतालों में ऑपरेशन तक टालना पड़ता है और मरीजों को मेडिकल कॉलेजों में रेफर करना पड़ रहा है। इसके बावजूद अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों का बड़ा हिस्सा मुख्यालय में प्रशासनिक कार्यों में लगा हुआ है। जिन विशेषज्ञों की सबसे अधिक जरूरत जिला अस्पतालों

कितने पद खाली

रेडियोलॉजिस्ट : 150 में 128 पद खाली (85.33 प्रतिशत), दंत विशेषज्ञ: 87 में 66 पद खाली (75.86 प्रतिशत), सर्जरी विशेषज्ञ :631 में 437 पद खाली (69.25 प्रतिशत), एनेस्थीसिया विशेषज्ञ : 644 में 441 पद खाली (68.48 प्रतिशत), मेडिकल विशेषज्ञ : 682 में 454 पद खाली (66.57 प्रतिशत), शिशु रोग विशेषज्ञ : 857 में 463 पद खाली (54.03 प्रतिशत) ।

संचालनालय में वर्षों से जमे विशेषज्ञ

संचालनालय में पदस्थ डॉक्टरों की सूची बताती है कि कई विशेषज्ञ लंबे समय से मुख्यालय में ही कार्यरत हैं। इसमें डॉ. अर्चना मिश्रा - स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. प्रज्ञा तिवारी - स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. राजश्री बजाज - स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. प्रभाकर तिवारी - शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉ. रूबी खान - पैथोलॉजिस्ट, डॉ. अर्चना पुंडीर - नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. शरद तिवारी - प्रिवेंटिव मेडिसिन विशेषज्ञ, डॉ. आदर्श महेश शुक्ल - एनाटॉमी विशेषज्ञ, डॉ. हर्ष राय - शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. संजय खरे - मेडिकल विशेषज्ञ, डॉ. योगेश कौर - ईएनटी विशेषज्ञ, डॉ. हेमेंद्र सिंह कदम - ईएनटी विशेषज्ञ, डॉ. प्रतिभा अहिरवार - दंत रोग विशेषज्ञ, डॉ. सौरभ कुमार - प्रिवेंटिव मेडिसिन, डॉ. राहुल सिंह भदौरिया - ट्रांसप्यूजन मेडिसिन, डॉ. तेज बहादुर सिंह - ट्रांसप्यूजन मेडिसिन, डॉ. राजू निदारिया - एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, डॉ. शिरीष रघुवंशी - महिला रोग विशेषज्ञ, डॉ. स्मृति सिंह - प्रिवेंटिव मेडिसिन, डॉ. नितिन पटेल - रेडियोलॉजिस्ट, डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव - प्रिवेंटिव मेडिसिन और डॉ. बी.एल. यादव - शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल है। इसमें कुछ प्रशासनिक कैडर में आ गए हैं।

मंत्री राकेश सिंह का कड़ा संदेश

अवैध खनन माफिया सावधान नहीं छिनेगा किसानों का हक

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने नर्मदापुरम दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। बलराम कृषि महोत्सव और भारतीय जनता पार्टी की कोर समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तवा और नर्मदा नदी क्षेत्र में

प्रतिबंध के बावजूद जारी अवैध रेत उत्खनन की शिकायतों पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए और इस गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

9 हजार न्यूनतम पेंशन की भी उठी मांग

पेंशनरों ने मांगा 27 माह का बकाया एरियर सीएस और एसीएस फायनेंस को भेजा ज्ञापन

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश के पेंशनरों ने एक बार फिर अपने लंबे समय से लंबित आर्थिक अधिकारों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव (वित्त) को पत्र भेजकर केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 माह के बकाया एरियर का भुगतान शीघ्र करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि जब शासकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से वित्तीय लाभ दिया गया, तो उसी आधार पर पेंशनरों को भी समान लाभ मिलना चाहिए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना और संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार पेंशनरों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन लागू करने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश को भेजा था। इसके बावजूद मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए 1 अप्रैल 2018 से संशोधित पेंशन लागू की, जिससे 27 माह का एरियर रोक दिया गया। उनका दावा है कि यह निर्णय संवैधानिक व्यवस्था और समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

पेंशनरों के हितों पर लगातार कुठाराघात

प्रांतीय सचिव यशवंत सिंह बैस और भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग लगातार पेंशनरों के आर्थिक हितों की उपेक्षा कर रहा है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति द्वारा महंगाई, जीवन-यापन की लागत और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 7,750 रुपये प्रतिमाह तय कर दिया, जो सातवें वेतन आयोग की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

मेट्रो एंकर | **आपदा से लड़ने को तैयार मध्यप्रदेश पुलिस**

90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के बाद 44 जवान बने राहत के नए प्रहरी

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश पुलिस के राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) में प्रतिनियुक्त जवानों का 90 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। समापन समारोह में महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी 44 जवानों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम तीन प्रशिक्षार्थियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि एसडीईआरएफ मध्यप्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण इकाई है, जो प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि इस विशेष प्रशिक्षण से जवानों की तकनीकी दक्षता, कार्यकुशलता और आपदा से निपटने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अधिक प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे।

उन्होंने प्रशिक्षित जवानों से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग पूरी संवेदनशीलता, समर्पण और सेवा भावना के साथ जनहित में करने का आह्वान किया। 90 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण में 44 जवानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

शहीद जवान की पत्नी बनीं प्रेरणा की मिसाल

इस प्रशिक्षण की सबसे प्रेरणादायक बात भिंड जिले में आपदा राहत कार्य के दौरान शहीद हुए एसडीईआरएफ जवान की धर्मपत्नी डॉली कुशवाह की सहभागिता रही। उन्होंने न केवल प्रशिक्षण में हिस्सा लिया, बल्कि उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सेवा, साहस और समर्पण का प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उनका यह कदम राष्ट्रसेवा के प्रति अटूट निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया। समापन समारोह में उप पुलिस महानिरीक्षक अमित सांधी, संभागीय सेनानी संगीता डी. कुमार, कमलेंद्र परिहार सहित एसडीईआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि प्रशिक्षित जवान भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों की जान बचाने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

तारीखों पर टिका न्याय

न्यायालय की चौखट पर खड़ा व्यक्ति केवल एक फैसला नहीं मांगता, वह अपने जीवन का वह हिस्सा वापस चाहता है जो मुकदमों की अंतहीन प्रतीक्षा में उससे छिन गया। मगर विडंबना यह है कि हमारे यहां न्याय का रास्ता अक्सर इतना लंबा हो जाता है कि फैसला आने तक कई लोगों की उम्र, उम्मीद और आर्थिक सामर्थ्य तीनों चुक जाती हैं। अदालतों की फाइलों में दबे लाखों मुकदमे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि अधूरी जिंदगियों का मौन इतिहास हैं। हाल ही में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों ने भारतीय न्याय व्यवस्था की उस तस्वीर को फिर सामने ला दिया है, जिसे हर नागरिक किसी न किसी रूप में महसूस करता है। सर्वोच्च न्यायालय में हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं, जबकि देशभर की अदालतों में करोड़ों मुकदमे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई प्रकरण ऐसे हैं जो दो और तीन दशक से भी अधिक समय से अंतिम निर्णय की राह देख रहे हैं। सवाल यह नहीं कि मुकदमे कितने हैं, बल्कि यह है कि क्या न्याय इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी अपने मूल अर्थ को बचाए रख पाता है? न्याय में देरी केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक पीड़ा का विस्तार है। एक ओर पीड़ित न्याय की आस में अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, दूसरी ओर विचाराधीन कैदी बिना अंतिम निर्णय के वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे जीवन बिताने को विवश हो जाते हैं। परिवार टूटते हैं, रोजगार छूटते हैं और लोगों की जीवनभर की कमाई कानूनी लड़ाई में समाप्त हो जाती है। ऐसे में न्याय का मूल्य केवल कानूनी नहीं, मानवीय भी हो जाता है। अक्सर इस संकट का कारण न्यायाधीशों की कमी और कमजोर आधारभूत ढांचे को बताया जाता है। निस्संदेह यह एक बड़ी समस्या है। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, जिससे मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है। लेकिन यह तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। जांच एजेंसियों द्वारा समय पर साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाना, बार-बार स्थगन, सरकारी विभागों की अनावश्यक अपीलें और प्रक्रियागत जटिलताएं भी न्याय की गति को धीमा करती हैं। यदि अदालतों से फैसला नहीं, केवल अगली तारीख मिलती रहे, तो यह विश्वास धीरे-धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत केवल न्याय देने की नहीं, बल्कि समय पर न्याय सुनिश्चित करने की है।

भारतवर्ष की सांस्कृतिक - आध्यात्मिक चेतना और कांवड़ यात्रा में शिवभक्ति का महाकुंभ

ओ.पी. पाल
स्तंभकार

भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना में श्रावण (सावन) मास का स्थान अत्यंत विशिष्ट एवं सर्वोपरि है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड तपन के उपरांत जब आकाश से मेघों की प्रथम बूंदें धरा का आलिंगन करती हैं, तब न केवल प्रकृति का नवश्रृंगार होता है बल्कि सनातन धर्मी चेतना भी देवाधिदेव महादेव की भक्ति में सराबोर हो उठती है। श्रावण का संपूर्ण मास भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना को समर्पित होता है। इस पावन अवसर पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा देश 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गुंजायमान रहता है। इस माह में आयोजित होने वाली 'कांवड़ यात्रा' केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अगाध श्रद्धा, कठिन तपस्या, सामाजिक समरसता और अनुशासन का अप्रतिम महासंगम है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की दृष्टि में शिव तत्व और श्रावण मास सनातन शास्त्रों एवं पुराणों (विशेषकर शिव पुराण और लिंग पुराण) के अनुसार, श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है।

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं अपितु यह भारत की अक्षुण्ण सांस्कृतिक धरोहर, अटूट आस्था और जीवंत सामाजिक व्यवस्था का दिग्दर्शन है। जहाँ एक ओर भक्त अपनी कठोर साधना से आत्म-शुद्धि करते हैं, वहीं, भारत की आत्मा उसकी सामूहिक चेतना और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना में निवास करती है। गंगाजल की हर बूंद के साथ उठने वाला शिवभक्तों का विश्वास भारत की एकता और अखंडता को सदैव संबल प्रदान करता रहेगा। वहीं, मान्यता है कि समूह में 'हर-हर महादेव' के निरंतर संकीर्तन से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोनों का स्राव करती हैं, जिससे शारीरिक थकावट का अहसास कम होता है और मानसिक तनाव दूर होता है।

सनातन धर्म में पौराणिक मान्यता है कि देवों और दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन के दौरान जब कालकूट नामक भयानक विष निकला, तो उसकी तपन से समस्त सृष्टि त्राहि-त्राहि कर उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान शिव ने उस हलाहल को कण्ठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कण्ठ नीला पड़ गया और वे 'नीलकंठ' कहलाए। विष की तीव्र दाहक अग्नि को शांत करने के लिए सभी देवी-देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक किया। इसी घटना की स्मृति में आज भी श्रद्धालु श्रावण मास में, विशेष रूप से श्रावण शिवरात्रि के दिन, गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।

एक अन्य मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में ही कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने प्रसन्न होकर इसी माह में उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था। इसलिए यह मास शिव-शक्ति के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरु हुआ। इसके तहत श्रद्धा, संकल्प और कठिन तपस्या का मार्गकांवड़ यात्रा एक ऐसी पैदल यात्रा है जिसमें भक्त (कांवड़िये) पवित्र नदियों मुख्यतः माँ गंगा नदी से जल भरकर अपने कंधों पर कांवड़ (बांस की बहंगी जिस पर जल के पात्र बंधे होते हैं) लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्थानीय या प्रसिद्ध शिवालयों तक पहुंचते हैं।

वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण: कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के नियमों के पीछे केवल आध्यात्मिक कारण ही नहीं बल्कि गूढ़ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी निहित हैं। वर्षा ऋतु में जल का प्राकृतिक शोधन की दृष्टि से श्रावण मास में नदियाँ उफान पर होती हैं और उनमें ताजा जल बहता है। प्राचीन काल में प्राकृतिक स्रोतों के जल की शुद्धता को पूजने और जल संरक्षण का संदेश देने के लिए जल यात्रा की परंपरा बनी। आयुर्वेद और कायिक शुद्धि (Detoxification): सावन के महीने में वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे मानव शरीर की जठराग्नि (पाचन क्रिया) मंद हो जाती है। इस माह में उपवास रखना, सात्विक भोजन करना और पैदल चलना शरीर की चयापचय प्रणाली को संतुलित करता है। इसके अलावा समूह में 'हर-हर महादेव' के निरंतर संकीर्तन से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोनों का स्राव करती हैं, जिससे शारीरिक थकावट का अहसास कम होता है और मानसिक तनाव दूर होता है।

गंगाजल उठाने के प्रमुख स्रोत स्थान: उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब) के लाखों कांवड़िये हरिद्वार के हर की पौड़ी और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से पवित्र गंगाजल उठाते हैं। वहीं कठिन तपस्या करने वाले 'डाक कांवड़िये' या सिद्ध भक्त सीधे गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री व गोमुख (उत्तराखंड) से जल लाते हैं। इसी प्रकार पूर्वी भारत की सुल्तानगंज (बिहार) में प्रसिद्ध उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाकर शिवभक्त कठिन पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय शिवभक्त हरिद्वार व ऋषिकेश के अलावा यूपी में ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) व नरौरा गंगा घाटों से जल भरकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। जबकि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कांवड़िये प्रयागराज और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के संगम स्थल से जल उठाकर बाबा विश्वनाथ (काशी) को अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए खास बात ये है कि कांवड़ यात्रा का सबसे सुंदर पहलू इसका कठोर अनुशासन है। यात्रा के दौरान कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि कांवड़िया विश्राम करता है तो कांवड़ को विशेष स्टैंड (आसन) पर रखा जाता है। पूरी यात्रा के दौरान शुद्ध सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य का पालन और मुख से निरंतर प्रभु नाम का संकीर्तन अनिवार्य होता है।

देश के प्रमुख राज्यों में शिवालय: श्रावण मास और श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर देश के कोने-कोने में स्थित ज्योतिर्लिंगों और ऐतिहासिक मंदिरों में विशाल मेले लगते हैं और जलाभिषेक किया जाता है। इनमें प्रमुख रुप से उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ (वाराणसी), लोधेश्वर महादेव (बाराबंकी), औघड़नाथ (मेरठ), पुरा महादेव (बागपत) में करोड़ों शिवभक्त काशी विश्वनाथ में मोक्षदायिनी गंगा से तथा मेरठ व बागपत में हरिद्वार से लाए जल से लाखों शिवभक्त जलाभिषेक करते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर (उज्जैन) और ओंकारेश्वर (खंडवा) मंदिरों में श्रावण के प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकलती है और कोटितीर्थ के जल से अभिषेक होता है। जबकि झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) और बिहार में सुल्तानगंज से 105 किमी पैदल चलकर कांवड़िये 'कामना लिंग' पर जल अर्पित करते हैं।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

बांकीपुर में करिश्मा करने वाले प्रशांत किशोर क्या बदल सकेंगे बिहार की सियासत...

राधा रमण
स्तंभकार

प्रशांत किशोर ने पटना के बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव में वह करिश्मा कर दिखाया, जिसकी बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों को उम्मीद नहीं थी। बांकीपुर का चुनाव परिणाम महज एक विधानसभा का चुनावी नतीजा नहीं माना जाना चाहिए। यह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई वह सीट है, जिस पर नितिन नवीन और उनके स्वर्गीय पिता नवीन किशोर सिन्हा का पिछले 30 वर्षों से कब्जा था। प्रशांत किशोर ने महज 30 दिनों की मेहनत से बड़ा उलटफेर कर दिया।

यह सब अचानक नहीं हुआ। बेशक, इसके लिए प्रशांत किशोर को अपना सौ प्रतिशत देना पड़ा। सनद रहे कि पानी सौ डिग्री पर उबालने पर ही वाष्प बनता है। नौ महीने पहले बिहार विधानसभा के चुनाव में जनसुराज के 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी थी। महज दो उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए थे। हालांकि तब भी जनसुराज को 3.4 फीसदी वोट जरूर मिले थे। किसी नयी-नवेली पार्टी के लिए यह कम नहीं है। राजनीति के जानकार भी यह समझ नहीं सके। उधर, जनसुराज की करारी हार से पक्ष-विपक्ष दोनों खुश थे। जनसुराज ने अपना कोर मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पलायन को ही बनाया था। आज भी जनसुराज से जुड़े लोग उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं।

बांकीपुर उपचुनाव में इस बार सबसे कम मतदान हुआ था। 3 लाख 79 हजार मतदाताओं वाले बांकीपुर में इस बार महज 1,30,246 लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें से 64,151 मत अकेले प्रशांत को मिले। भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा गुप्ता को 14,273 मत मिले। शेष बचे 22 उम्मीदवारों में से प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन श्रीवास्तव को सबसे अधिक 973 तो निर्दलीय ब्रजेश पटेल को सबसे कम महज 70 वोट मिले। 646 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रशांत हताश होकर घर नहीं बैठे। वह पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम पहुंचे, जहां से गांधीजी ने अंग्रेजों के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने 24 घटे का मौन व्रत किया फिर कहा कि वह लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बिहार में घर-घर तक जाएंगे। जनसुराज की लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि बिहार बदलने की है। बिहार में खुशहाली लाना ही उनका ध्येय है। उन्होंने अपने जीवन का 10 साल बिहार के विकास के लिए समर्पित करने का फैसला किया है। उन्होंने दिल्ली का अपना आवास छोड़कर अपने 20 वर्षों की अर्जित कमाई का 90 फीसदी जनसुराज को दान कर दिया। कहा, आगे भी वह जो कमाएंगे, उसका 90 फीसदी जनसुराज का होगा। उन्होंने लोगों से भी कम से कम 1000 रुपये जनसुराज को दान करने की अपील की।

बाद के दिनों में लोगों ने देखा कि चाहे पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला हो, पटना के ही बंटी यादव की हत्या अथवा आरा के बेलौटी गांव के भारत भूषण तिवारी की हिरासत में लेकर हत्या, प्रशांत किशोर हर जगह पहुंचे और पीड़ितों के आंसू पोंछे। पटना में पिछले माह छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ उन्होंने हुंकार भरी। जबकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की हार से इतने हताश हुए कि विधानसभा की बैठकों में भी कम ही जाते हैं। इसका सीधा लाभ बांकीपुर के उप चुनाव में प्रशांत किशोर को मिला। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के पास पेड वर्करों का भारी जमावड़ा था। इस बार बांकीपुर में प्रशांत ने समर्पित कार्यकर्ताओं को साथ लिया। इनमें अधिकांश युवा थे जो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। प्रशांत खुद मोहल्लावासियों के साथ देर रात तक बैठते थे। उन्होंने चुनाव में नीतीश कुमार की सक्रिय भागीदारी नहीं होने और भाजपा द्वारा नीतीश कुमार को दरकिनार करने का मुद्दा उठाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया।

बिहार विधानसभा चुनाव में महज 25 सीटों पर सिमट जानेवाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में बांकीपुर के परिणाम से घबराहट है। सांसद मीसा भारती प्रशांत किशोर को भाजपा का असली उम्मीदवार बता रही हैं, जबकि उनकी बहन रोहिणी आचार्य प्रशांत किशोर को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए तेजस्वी पर तंज कस रही हैं। 30 जुलाई को जीत का दावा करने वाले तेजस्वी अब हकलाये फिर रहे हैं।

बिहार में पिछले 35 वर्षों से लालू यादव राजनीति के केंद्र में रहे हैं। राज्य में लालू समर्थन और लालू विरोध की सियासत होती रही है। यह अलग बात है कि बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत के कारण कुछ वर्षों से लालू महज तमाशबीन बने हुए हैं। पार्टी का सारा काम तेजस्वी ने संभाल लिया है। यहां तक कि उमीदवारों का चयन भी अब टीम तेजस्वी ही कर रही है। राजद के सिमटते जन समर्थन का यह बड़ा कारण है। ऐसे में सफल चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर क्या बिहार की सियासत का नया केंद्र बनेंगे, समय बताएगा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी तथा तमिलनाडु में टी जोसेफ विजय के अभ्युदय के बाद इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अलर्ट

शरीर की हर गांठ कैंसर नहीं, लेकिन स्किन का रंग बदले तो हो जाएं सावधान

शरीर में किसी भी जगह अचानक गांठ महसूस होना स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ा सकता है। कई लोग इसे सीधे कैंसर से जोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग महीनों तक इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर में बनने वाली अधिकांश गांठें सौम्य होती हैं और उनका कैंसर से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी हर नई या लगातार बनी रहने वाली गांठ का सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

क्लीवलैंड क्लीनिक के अनुसार गांठ बनने के कई कारण हो सकते हैं और हर कारण गंभीर नहीं होता। कई बार त्वचा के नीचे फैट जमा होने से लिपोमा बन जाता है, जो आमतौर पर मुलायम और दर्द रहित होता है। वहीं त्वचा में तरल पदार्थ भर जाने से सिस्ट बन सकती है। इसके अलावा संक्रमण के दौरान लिम्फ नोड्स में सूजन, चोट लगने के बाद रक्त जमा होना, हार्मोनल बदलाव या कुछ मामलों में ट्यूमर भी गांठ बनने का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गांठ की प्रकृति, उसका आकार, स्थान, बढ़ने की गति और उससे जुड़े अन्य लक्षण यह तय करने में मदद करते हैं कि स्थिति सामान्य है या आगे जांच की आवश्यकता है।

सामान्य गांठ धीरे-धीरे बढ़ती है, छूने पर आसानी से इधर-उधर हिल जाती है। मुलायम या रबड़ जैसी महसूस होती है और लंबे समय तक आकार में बदलाव नहीं होता।अन्य गंभीर लक्षण नहीं होते। जबकि गंभीर जांच की जरूरत वाली गांठ का तेजी से आकार बढ़ता है। बहुत कठोर होना, त्वचा या अंदरूनी ऊतकों से चिपकी होना, कई सप्ताह तक बनी रहना, बिना दर्द के लगातार बढ़ना और त्वचा का रंग बदलना या घाव बन जाना आदि लक्षण होते हैं। क्लीवलैंड के अनुसार यदि गांठ पत्थर जैसी सख्त महसूस हो और दबाने पर अपनी जगह से न हिले, तो डॉक्टर इसकी विस्तृत जांच करने की सलाह दे सकते हैं।

नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक यदि बिना किसी कारण वजन घट रहा हो, रात में अत्यधिक पसीना आता हो या लंबे समय तक बुखार बना रहे, तो गांठ की जांच जरूरी हो जाती है क्योंकि ये कुछ गंभीर बीमारियों के साथ जुड़े लक्षण हो सकते हैं। सही जानकारी और समय पर चिकित्सकीय सलाह ही अनावश्यक डर और संभावित जटिलताओं, दोनों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है।

निशाना

टूटे हुए दो पर देखे...

प्रदीप कश्यप

जो सच्चे लोग हैं वे झूठ से निडर देखे।
हरेक दिल पे उनकी बातों के असर देखे।
उड़ान भरना था आकाश में जिन्हें खुलकर।
उन्हीं परिंदों के टूटे हुए दो पर देखे।
सभी ने मार के पत्थर उन्हें किया घायल।
फलों से खूब भरे हमने जो शज़र देखे।
अमीर लोगों की देखी हवेली ऊँची फिर।
दुखी गरीबों के झुग्गी के जैसे घर देखे।
लड़ाई जिनको सितमगर से खूब करना थी।
सभी ने आँखों में उनकी सहम ते डर देखे।
हवा को छोड़ के कुछ भी नहीं वहाँ पाया।
अहं के हमने जो ऊँचे बढ़े शिखर देखे।
दुखों के साथ में कश्यप गुजारें जो जीवन।
सुखों की बात कोई उनसे भी तो कर देखे।

टेक्नो अपडेट

एग्रीवोल्टिक्स तकनीक से खेत में लगाए सोलर पैनल, बिजली फ्री, फसल भी अच्छी

खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसान एक ही जमीन से तीन बड़े फायदे उठा सकते हैं। फसल की पैदावार, फ्री बिजली और खेत से अतिरिक्त कमाई। खेती करने और सोलर पावर पाने का एक नया तरीका मैसाचुसेट्स के किसान ने निकाल लिया है। यह कुछ और नहीं बल्कि एग्रीवोल्टिक्स तकनीक का एक उदाहरण है, जो खेती का एक नया तरीका है। इसके तहत खेती और बिजली एक ही जमीन से बनाई जा रही है। साथ ही, इससे यह भी पता चला है कि सोलर पैनल को केवल घर की छत पर नहीं लगाया जा सकता है। सोलर पैनल को खेतों पर लागकर इससे ना सिर्फ बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि अच्छी खेती भी की जा सकती है।

किसान ने अपने खेत में ही सोलर पैनल लगाए हैं। हालांकि, यह आम सोलर पैनल नहीं है। जी हां, खेत में आम सोलर पैनल लगाने के बजाय, ट्रैकिंग सोलर सिस्टम लगाया गया है। बता दें कि कई जगह ट्रैकिंग सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जो सूरज की दिशा के साथ घूमते हैं, ताकि फसलों को जरूरत के हिसाब से धूप और छाया दोनों मिलती रहे। इंजीनियर इस सिस्टम को को जमीन से लगभग 9.8 फीट ऊपर लगाते हैं। रिसर्चर्स ने पैनल के नीचे मौसम की स्थितियों पर नजर रखी और सेंसर से पता चला कि ऊंचे स्ट्रक्चर की वजह से वहां का मौसम काफी ठंडा रहा। पैनल ने दोपहर की तेज धूप को फिल्टर किया, जिससे मिट्टी का तापमान कम हुआ और खेतों में हवा के बहाव में बदलाव आया। सबसे जरूरी बात यह है कि छाया की वजह से जमीन ज्यादा समय तक नमी वाली रही, जिससे गर्मी के दिनों में बेरी के पौधों में पानी की कमी नहीं हुई। माना जाता है कि ऊंचे पैनल तेज धूप से सीधे संपर्क को कम करने और पानी बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण को धीमा करने में मदद करते हैं।

ड्डु प्रोजेक्ट यह भी दिखाता है कि एक जमीन पर ही खेती करना और बिजली बनाने से पता चला है कि खेती को गर्म होते मौसम के हिसाब से ढलने में कैसे मदद कर सकते हैं। बड़े सोलर पैनल मिट्टी को ठंडा रखते हैं और पानी की बर्बादी कम करते हैं, जिससे सिंचाई की जरूरत घटती है और फसलें गर्मी के तनाव से बची रहती हैं।

वायरल कंटेंट

बीटेक करने के बाद भी चला रहा रेपिडो राइड खत्म होते ही यात्री से मांगी नौकरी

आज के समय में अच्छी शिक्षा हासिल करना जितना जरूरी है, उतना ही मुश्किल उसके बाद मनचाही नौकरी पाना भी हो गया है। हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स पूरे करके नौकरी की उम्मीद में निकलते हैं, लेकिन सभी को तुरंत अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे ही एक युवक की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने अपनी परिस्थितियों से हार मानने के बजाय हर संभव कोशिश जारी रखी। वायरल पोस्ट के मुताबिक, एक युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल रेपिडो राइडर के रूप में काम कर रहा है। वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ लगातार नौकरी की तलाश भी कर रहा है। इसी दौरान उसकी एक सवारी पूरी हुई, जिसके बाद उसने यात्री को एक विनम्र संदेश भेजा। उस संदेश में उसने बताया कि उसने वर्ष 2024 में क्ब्अद्दष्द्ध की पढ़ाई पूरी की है, वह फ्रेशर है और यदि कहीं नौकरी का अवसर हो तो कृपया उसकी मदद की जाए। यात्री ने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय दी। कई यूजर्स ने युवक की हिम्मत और सकारात्मक सोच की सराहना की। लोगों का कहना था कि उसने किसी तरह की गलत मांग नहीं की, बल्कि सम्मानजनक तरीके से अपने लिए एक अवसर मांगा। कई लोगों ने यह भी लिखा कि आज के दौर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हर छोटा मौका मायने रखता है।

हालांकि, इस मामले पर सभी की राय एक जैसी नहीं रही। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि राइड पूरी होने के बाद ग्राहक के निजी नंबर पर नौकरी के लिए संदेश भेजना कितना उचित है। उनका मानना था कि मदद मांगने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जिससे किसी की निजता प्रभावित न हो। वहीं दूसरी ओर, कई यूजर्स ने कहा कि युवक की मंशा सिर्फ रोजगार ढूंढ़ने की थी और उसकी परिस्थिति को समझने की जरूरत है। यह घटना एक बार फिर देश में रोजगार की स्थिति और फ्रेशर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा का कारण बन गई।

न्यूज विंडो

दुकानों की मिठाईयों की शुद्धता जांची, साफ-सफाई के दिए निर्देश

सिरोंज। रक्षाबंधन से पहले आमजन को शुद्ध मिठाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को नगरपालिका की टीम मुख्य बाजार पहुंची। सीएमओ रामप्रकाश साहू और स्वास्थ्य निरीक्षक मनीष सिंह के नेतृत्व में टीम ने मिठाई दुकानों की साफ-सफाई देखी। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच की। टीम बाजार की प्रमुख मिठाई दुकानों पर पहुंची। मिठाइयों की गुणवत्ता देखी। रख-रखाव की जांच की। दुकानों की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। दुकानों में लगी पानी की टंकी भी जांची गई। दुकानदारों को पानी पीने योग्य पाए जाने संबंधी जांच कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि मिठाई बनाने और बेचने में पूरी स्वच्छता रखें। बासी और मिलावटी मिठाई बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान टीम मानक पॉलीथिन का नमूना भी साथ लेकर गई। सीएमओ रामप्रकाश साहू ने दुकानदारों को अमानक पॉलिथीन का उपयोग न करने की हिदायत दी। कहा, मिठाई पैकिंग में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार पॉलिथीन ही इस्तेमाल करें। अमानक और प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर जुर्माना लगेगा। नगरपालिका की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने साफ-सफाई रखने और मानकों का पालन करने का आश्वासन दिया।

मेडिकल सुविधा पर सवाल श्रम विभाग से जांच की मांग

उमरिया। उमरिया जिले की पाली तहसील क्षेत्र में स्थित मंढार पावर प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के PF, ESI और मेडिकल सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा PF और ESI से संबंधित राशि एवं रिकॉर्ड का स्पष्ट हिसाब उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पावर प्लांट में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन से PF एवं ESI के नाम पर कितनी राशि काटी जा रही है, कितनी राशि संबंधित खातों में जमा की गई और उसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। ठेका कर्मचारियों ने मेडिकल सुविधा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों के अनुसार, उन्हें ESI के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और संबंधित प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में श्रम विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग उठ रही। ठेका कर्मचारियों ने श्रम विभाग से मांग की है कि केवल कागजी रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वेतन रिकॉर्ड, PF/UAN विवरण, ESI रिकॉर्ड, बैंक भुगतान और ठेका कंपनी के दस्तावेजों का आपस में मिलान कर जमीनी स्तर पर जांच की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनके वेतन से PF या ESI की राशि काटी गई है तो उसका पूरा हिसाब उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार सामाजिक सुरक्षा और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

गंज हनुमान मंदिर पर प्रतिदिन हो रहे पार्थिव शिवलिंग निर्माण

गंजबासौदा। श्रावण मास की पावन बेला में गंज हनुमान मंदिर पर प्रतिदिन श्रद्धा और आस्था के साथ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण एवं विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचकर मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और भगवान भोलेनाथ का दुग्ध, जल, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और लोककल्याण की कामना कर रहे हैं। मंदिर में प्रतिदिन भक्तिमय वातावरण बना रहता है। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोषों से पूरा परिसर शिवमय हो जाता है। महिला, पुरुष, युवा और बच्चे पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण में भाग लेकर धार्मिक पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पंडित विष्णु शर्मा ने बताया कि मंदिर समिति के अनुसार श्रावण मास भर यह धार्मिक आयोजन नियमित रूप से जारी रहेगा। श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं भगवान शिव की आराधना में सहभागी बनने का आग्रह किया गया है। श्रावण माह में चल रहे इस आयोजन से मंदिर परिसर में प्रतिदिन आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है।

मर्यादा और अनुशासन से ही संवरता है भविष्य: डॉ. सक्सेना

गंजबासौदा। स्थानीय एलबीएस कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, विभिन्न विभागों की गतिविधियों तथा उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कॉमर्स विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज सक्सेना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन, मर्यादा और नैतिक मूल्यों का पालन सफलता की पहली शर्त है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे मर्यादित रहें, सभी प्रकार की वर्जनाओं से बचें तथा अध्ययन के साथ प्राध्यापकों और वरिष्ठ विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का लाभ लेकर अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करें। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीयूष दुबे ने विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के अंतर को समझाते हुए कहा कि कॉलेज में नियमित उपस्थिति और सतत मूल्यांकन प्रणाली का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही गंभीरता के साथ अध्ययन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन का लक्ष्य रखना चाहिए। कॉमर्स विषय विशेषज्ञ प्राध्यापक कुलेन्द्र श्रीवास्तव ने बीकॉम संकाय में उपलब्ध करियर संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक सारिका देव ने किया, जबकि रुबिना ठाकुर ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र का मामला, लोगों में आक्रोश

देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने पांच गौवंशों को कुचला, मौके पर मौत, चालक फरार

शहडोल। दोपहर मेट्रो

शहडोल में सड़क हादसों में बेजुबान गौवंशों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र का है, जहां भारत पेट्रोल पंप के सामने बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर बैठे पांच गौवंशों को कुचल दिया। हादसे में सभी गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो मवेशी ट्रेलर के पहियों के नीचे फंस गए, जिससे चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर बुढार से शहडोल की ओर जा रहा था। हादसे के बाद वाहन घटनास्थल पर ही खड़ा रह गया, जबकि उसके आगे और पीछे पांच मवेशियों के शव पड़े रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के कई घंटे बाद तक न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही यातायात विभाग की टीम ने वाहन हटाने या यातायात सामान्य कराने की कोई कार्रवाई की।

ग्रामीणों का कहना है कि भारत पेट्रोल पंप के सामने अक्सर भारी वाहनों की कतार

लगी रहती है। दूसरी ओर सड़क पर गौवंशों का बैठना आम बात है। ऐसे में यह स्थान लगातार हादसों का कारण बन रहा है। लोगों का आरोप है कि पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे दिन-रात खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने के लिए यातायात विभाग ने आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी स्थान पर पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है। इसके बावजूद न तो अवैध पार्किंग पर रोक लगाई गई और न ही गौवंशों को सड़क से हटाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की गई।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हादसे की जांच कर ट्रेलर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पेट्रोल पंप के सामने अवैध रूप से खड़े वाहनों पर सख्ती और गौवंशों को सड़क से हटाने के लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो। वहीं, थाना प्रभारी सोहागपुर आर पी रावत ने कहा जानकारी मिली है, हम दिखवाते हैं। खैर उपेक्षित गौवंशों को ऐसी दुर्घटनाओं के बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिससे आए दिन सड़कों पर बैठे गौवंशों की असमय मौत की खबरें आती रहती हैं। सरकार और समाज के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। बचाव के लिए समुचित प्रयास की आवश्यकता है।

पचमा रोड पर यातायात पुलिस की सख्ती

चैकिंग अभियान में वाहन चालकों पर कार्रवाई कर वसूला जुर्माना

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में पचमा रोड पर यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 10 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 3,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया चलाने, आवश्यक दस्तावेज साथ न रखने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की। कार्रवाई के साथ-साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया तथा भविष्य में नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। यातायात प्रभारी निरपत सिंह लोधी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति

जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें तथा वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार नियमित रूप से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान राकेश साहू भी मौजूद रहे।

नर्मदापुरम में विशेष वाहन चेकिंग अभियान जारी

चार दिनों में 703 वाहनों पर की कार्रवाई 3.02 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिले में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और निजी वाहनों पर अवैध रूप से हूटर, फ्लैशर, वीआईपी व शासकीय स्टिकर, पदनाम, मोनोग्राम, ब्लैक फिल्म तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट के उपयोग पर रोक लगाने के लिए नर्मदापुरम पुलिस का विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 1 से 10 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के चौथे दिन भी जिलेभर में सघन वाहन जांच की गई। डीएसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि चौथे दिन 174 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 68,600 रुपये का समन शुल्क वसूला। वहीं अभियान के पहले चार दिनों में अब तक 703 वाहनों पर कार्रवाई कर 3 लाख 2 हजार 300 रुपये का समन शुल्क वसूला जा चुका है। वाहन जांच के दौरान निजी वाहनों पर लगे अवैध हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट, वीआईपी और शासकीय स्टिकर, अनधिकृत पदनाम, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा ब्लैक फिल्म के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। चौथे दिन 2 अवैध फ्लैशर लाइट, 22 ब्लैक फिल्म लगे वाहन, 36 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और 3 अनधिकृत पदनाम प्रदर्शित करने के मामलों में वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी चालान किए गए। यह अभियान पुलिस अधीक्षक साईंकृष्ण एस. थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) संतोष मिश्रा के नेतृत्व में जिलेभर में चलाया जा रहा है।

इटारसी जंक्शन के माल गोदाम को हटाने की मांग, राज्यसभा में गूंजा मुद्दा

सांसद माया नारोलिया ने कहा– गोदाम शिफ्ट होने में देरी से अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्य प्रभावित

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान इटारसी जंक्शन के पुराने रेल माल गोदाम को जल्द स्थानांतरित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इटारसी जंक्शन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन पुराने माल गोदाम को हटाने में हो रही देरी से स्टेशन के विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो रही है।

सांसद ने सदन में कहा कि योजना के तहत यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, नए फुट ओवर ब्रिज, विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग और स्टेशन परिसर के व्यापक विकास का कार्य प्रस्तावित है। मास्टर प्लान के अनुसार

स्टेशन परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित पुराने ढांचों को हटाया जाना है, जिसमें पुराने रेल माल गोदाम का स्थानांतरण भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर हो रही देरी के कारण माल गोदाम अब तक निर्धारित नए स्थान पर शिफ्ट नहीं हो सका है। इससे प्लेटफॉर्म विस्तार सहित अन्य निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

माया नारोलिया ने कहा कि जब तक पुराना रेल माल गोदाम पूरी तरह स्थानांतरित नहीं होगा, तब तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख विकास कार्यों को अपेक्षित गति नहीं मिल पाएगी। उन्होंने रेल मंत्री से मांग की कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी कर माल गोदाम का शीघ्र स्थानांतरण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि इटारसी जंक्शन के आधुनिकीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की चेतावनी मांगें पूरी नहीं हुईं तो संचालन होगा बंद

बालाघाट। दोपहर मेट्रो

बालाघाट में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने प्रशासन को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 7 अगस्त की रात से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उनकी प्रमुख मांगों में बसों का राष्ट्रीयकरण रोकने, रॉयल्टी का विरोध करने और यात्री किराए में वृद्धि करना शामिल है। ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार 7 जुलाई 2026 के राजपत्र के माध्यम से बसों का राष्ट्रीयकरण कर बस व्यवसाय को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए।ऑपरेटर्स ने 2021 के बाद यात्री किराए का निर्धारण न होने पर चिंता व्यक्त की, जबकि डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 6 जुलाई को टेंडर के माध्यम से बसों की रॉयल्टी लेने की तैयारी का भी विरोध किया गया है।

मेट्रो एंकर — बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह बोले-

भाजपा सरकार ने किसानों को सम्मान दिया, कांग्रेस राज में चली थीं गोलियां

इटारसी। दोपहर मेट्रो

कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज किसान अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो सरकार उसे सम्मान देती है, जबकि कांग्रेस शासन में किसानों को आंदोलन के दौरान गोलियां खानी पड़ी थीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश का सिंचित रकबा 7 लाख हेक्टेयर था, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक इसे एक करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का है।

प्रभारी मंत्री ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को देखते हुए किसानों को पानी की हर बूंद का सदुपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध खेती की आधारशिला है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से खेती को

लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और शासन की योजनाओं की जानकारी देने का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि एक समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, लेकिन भाजपा सरकार के नेतृत्व में विकास की नई दिशा मिली है। उन्होंने दावा किया कि किसानों के हित में मूंग खरीदी, खाद उपलब्धता और तीसरी फसल की खरीदी जैसे फैसले भाजपा सरकार ने किए हैं। कार्यक्रम में नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, सिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस. थोटा, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, एसडीएम निलेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम डॉ. यादव ने वर्चुअल माध्यम से दी बड़ी सौगातें

राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने किसानों के लिए सहकारिता विभाग की नई कवच योजना की घोषणा करते हुए बताया कि पहले चरण में करीब 5 हजार किसानों को राहत मिलेगी, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब धान और सरसों की फसलों को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा, जबकि उड़द पर बोनस जारी रहेगा। उन्होंने किसानों से फसल विविधीकरण अपनाने तथा उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और बकरी पालन जैसे क्षेत्रों से जुड़कर आय बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मोहासा–बाबई औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के औद्योगिक विकास का नया केंद्र बन रहा है और नर्मदापुरम में उद्यानिकी एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को भी प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा आयोजित करने की भी अपील की।

न्यूज विंडो

पुलिस ने कार्रवाई कर कंटेनर से 23 गौवंश को कराया मुक्त

सिवनी। जिले में गौ-वंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 23 गौ-वंश मुक्त कराए। इस दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 10 लाख रुपए कीमत का कंटेनर भी जब्त किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

नई दुकानें न मिलने के विरोध में मंदिर के मुख्य गेट पर दिया धरना

पांढुर्णा। सौंसर के जाम सावली स्थित प्रसिद्ध हनुमान लोक में नई दुकानों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। करीब 25 सालों से मंदिर परिसर के आसपास दुकान चला रहे व्यापारियों ने नई दुकानें न मिलने के विरोध में मंदिर के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने मंदिर समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने साथ न्याय की मांग की। उनका कहना है कि हनुमान लोक बनने के बाद जब नई दुकानें बनाई गईं, तो उन्हें उम्मीद थी कि इतने सालों से दुकान चलाने के नाते पहली तरजीह उन्हें ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे अब उनके सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, कामकाज ठप

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में सभी पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल के कारण जिले की सभी तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। संघ की मुख्य मांगों में कैडर रिव्यू, वेतन विसंगति दूर करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा, सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करना, लंबित मानदेय का भुगतान और स्थानांतरण नीति में सुधार शामिल हैं। पटवारियों ने साफ किया है कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी।

आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद

मंडला। जिले की नारायणगंज तहसील के ग्राम चिरईडोंगरी में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के अनुसार इन अवारा कुत्तों ने 25 से 30 लोगों को काट लिया। इनमें से 6-7 की हालत गंभीर है। वहीं अब बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बुधवार को शासकीय स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पुष्टि की कि गांव में बने भय के माहौल के कारण बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं बुलाया गया है। इसकी जानकारी पर्यवेक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को भी दे दी गई है। शाला प्रबंधन ने ग्रामीणों से अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती या प्रशासन की ओर से कुत्तों को पकड़ने की सूचना नहीं मिलती, तब तक बच्चों को स्कूल या बाहर न भेजें। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय से तत्काल कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।

वन माफिया सक्रिय: वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

झलौन वन परीक्षेत्र में फिर सामने आया सागौन की अवैध कटाई का मामला, लोगों में आक्रोश

तेंदूखेड़ा/झलौन। दोपहर मेट्रो

उपवन मंडल के अंतर्गत आने वाले झलौन वन परीक्षेत्र में बहुमूल्य सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे मामलों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और वन माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन माफिया लंबे समय से जंगलों में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वन विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि वन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में सागौन के पेड़ों की कटाई करते हैं और बड़े वाहनों के माध्यम से लकड़ी का परिवहन कर लेते हैं। कई मामलों में विभाग केवल वाहन और लकड़ी जब्त कर कार्रवाई का दावा करता है, जबकि मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल हो जाते हैं। इससे वन अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, ससना तिगड्डा के समीप बीट क्रमांक-169, उमरिया माल क्षेत्र में करीब 8 से 10 वन माफिया सागौन के एक बड़े पेड़ की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात दैनिक वनश्रमिकों ने पेड़ कटने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वनश्रमिकों को देखकर आरोपी अंधेरे का

लाभ उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। बताया जाता है कि आरोपी पेड़ को काटकर उसकी सिल्लियां भी तैयार कर चुके थे। नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर कुछ वनश्रमिकों ने बताया कि उन्होंने घटना की जानकारी तत्काल वन परीक्षेत्र अधिकारी को दी थी, लेकिन न तो वन परीक्षेत्र अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और न ही डिप्टी रेंजर अथवा अन्य जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उनका आरोप है कि समय पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने से वन माफियाओं को भागने का अवसर मिल गया। इसके बाद पूरी रात वनश्रमिकों को कटे हुए सागौन के पेड़ और तैयार की गई सिल्लियों की सुरक्षा करनी पड़ी। इस घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सूचना मिलने के बाद भी अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे तो इससे वन माफियाओं के हौसले और बुलंद होंगे। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि वन परीक्षेत्र अधिकारी सतीश मसीह ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्हें घटना की कोई सूचना नहीं मिली थी। उन्होंने दावा किया कि संबंधित सागौन का पेड़ पहले से ही लगभग 50 प्रतिशत कटा हुआ था और उसकी निगरानी के लिए उन्होंने पहले से ही वनश्रमिकों की ड्यूटी लगा रखी थी। उनका आरोप है कि कुछ कर्मचारी उन्हें जानबूझकर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस संबंध में झलौन वन परीक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि कटे हुए सागौन को विभाग द्वारा जब्त कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से झलौन परिसर लाया गया है। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद सागौन की सिल्लियां तेंदूखेड़ा वन डिपो भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में तेंदूखेड़ा उपवन मंडल अधिकारी प्रतीक दुबे ने कहा कि वे स्वयं झलौन पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

यह मामला एक बार फिर झलौन वन परीक्षेत्र में बहुमूल्य सागौन की सुरक्षा व्यवस्था और वन अपराधों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की निगाहें वन विभाग की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।

कटनी पुलिस ने राजस्थान के दो साइबर ठगों को किया गिरफ्तार

कटनी। दोपहर मेट्रो

कटनी के कुठला थाना पुलिस ने डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित अंकित राय ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने कटनी निवासी एक युवक के बैंक खाते से बिना अनुमति के यूपीआई के माध्यम से 1.88 लाख रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए थे। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

भगवा और संत-महात्माओं के कथित अपमान के विरोध में विहिप-बजरंग दल का प्रदर्शन, नरसिंहपुर में पुतला दहन

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा सुभाष पार्क चौराहे पर भगवा और संत-महात्माओं के कथित अपमान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव एवं कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध जताया और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू समाज के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भगवा केवल एक रंग नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। संत-महात्माओं के सम्मान पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी समाज स्वीकार नहीं करेगा। संगठन के

पदाधिकारियों ने कहा कि यदि भविष्य में भी सनातन धर्म, भगवा अथवा संत-महात्माओं का अपमान किया गया तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जनजागरण एवं विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सारसबगली में सार्वजनिक रास्ते के विवाद पर आक्रोश

तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण, मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

ब्लॉक की ग्राम पंचायत सारसबगली में सार्वजनिक रास्ते को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने 12 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के तीसरे दिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा जिससे अनशनकारी आक्रोशित हैं। ग्रामीण भी अनशन कारियों के सहयोग के लिए 24 घंटे अनशन स्थल पर बैठे रहते हैं।

अनशन पर बैठे ग्रामीणों में कमलेश पटेल, राहुल यादव, भोला बसोर प्रमुख रूप से शामिल ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर और तहसीलदार को पहले ही अवगत करा दिया था उन्होंने कहा था की रास्ता बंद नहीं होने देंगे हम लोगों ने कहा था कि यदि एक सप्ताह के भीतर रास्ता नहीं खुला तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाकर आवागमन पूरी तरह सुचारु नहीं

किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राहुल यादव का कहना है कि यह मार्ग लगभग 100 वर्षों से आम रास्ता बना हुआ है लेकिन एक व्यक्ति द्वारा जमीन खरीद लेने से उसने आम रास्ता बंद कर दिया है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई करने तथा सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल एक रास्ते का नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों के आवागमन और उनके अधिकारों से जुड़ा मामला है।

एसडीएम सीजी गोस्वामी ने बताया कि मैं आज पूरे दिन मीटिंग में व्यस्त रहा, अनशनकारियों से राज्यमंत्री के अनुज सतेंद्र सिंह ने बात कर समझाया था लेकिन अनशन कारी मान नहीं रहे हैं इसके अलावा जिस रास्ते की मांग की जा रही हैं उसका नाप भी करवा लिया गया हैं वह प्राइवेट रास्ता हैं। मैं जाकर फिर से अनशनकारियों से बात करता हूं।

आज राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

असम CRPF कैंप में गोलीबारी बालाघाट के हेड कांस्टेबल शहीद

बालाघाट। दोपहर मेट्रो

असम के नागांव जिले के कटिमारी स्थित 34वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप में गोलीबारी हुई। जिसमें जवान शहीद हो गए। गोलीबारी की घटना में बालाघाट के हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर आज गुरुवार को गृहग्राम पहुंचेगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

घटना 4 अगस्त की सुबह करीब 7: 30 बजे की है। सीआरपीएफ के अनुसार आंध्र प्रदेश निवासी एएसआई बल्लानी प्रेमाबरम ने गार्ड रूम से इंसास राइफल लेकर बैरक और क्वार्टर गार्ड की ओर फायरिंग कर दी। घटना में एसआई रामनवाल सिंह यादव और हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल की मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी एएसआई ने खुद को भी गोली मार ली। घटना में एएसआई माने गोबिंद घायल हुए हैं। शहीद विष्णु बघेल के पेट में गोली लगी थी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पदोन्नति के बाद उनका हाल ही में भोपाल की 107वीं बटालियन से असम की 34वीं बटालियन में तबादला हुआ था।

इकलौते बेटे की शहादत से परिवार सदमे में

शहीद विष्णु बघेल अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता पैरालिसिस से पीड़ित हैं, जबकि मां कैंसर का इलाज करा रही हैं। परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज गुरुवार को उनके पैतृक गांव भीकेवाड़ा (शेरपार) में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मेट्रो एंकर | **घंटों का इंतजार... पुलिस ने संभाली मानवीय जिम्मेदारी**

खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को पिलाया ठंडा पानी

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

कृषि उपज मंडी स्थित डबल लॉक खाद्य वितरण केंद्र पर किसानों की लगातार बढ़ती भीड़ और उन्हें हो रही असुविधा को देखते हुए तेंदूखेड़ा पुलिस ने मानवीय पहल करते हुए किसानों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था कराई। खाद्य वितरण के लिए बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही लाइन में लगे रहे। प्रशासन द्वारा खाद्य वितरण को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए तीन काउंटर संचालित किए गए, जहां किसानों को क्रमवार खाद्य उपलब्ध कराई गई। पिछले दो दिनों से खाद के लिए किसान लगातार परेशान हो रहे थे। तीसरे दिन भी लंबी कतारें लगी रहीं। लाइन में लगे किसानों को सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की हो रही थी। यदि कोई किसान पानी पीने के लिए लाइन से बाहर निकलता, तो दोबारा अपनी जगह पर लौटने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कई बार इस कारण किसानों के बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती थी।

किसानों की इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निरीक्षक के निर्देशन में पुलिस एवं नगर सैनिकों ने डबल लॉक परिसर में ठंडे पेयजल की व्यवस्था कराई। पुलिस कर्मियों ने स्वयं डिस्पोजल ग्लास में पानी भरकर कतार में खड़े किसानों तक पहुंचाया, ताकि उन्हें लाइन छोड़कर बाहर न जाना पड़े और खाद वितरण की प्रक्रिया भी प्रभावित न हो। इस दौरान पुलिस एवं

प्रशासनिक अमले ने खाद वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था पर भी नजर बनाए रखी। किसानों ने पुलिस विभाग की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी और लंबी प्रतीक्षा के दौरान पानी की व्यवस्था से उन्हें काफी राहत मिली। पुलिस की इस पहल ने यह संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखना भी पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। नगर निरीक्षक सरोज ठाकुर ने बताया कि खाद्य वितरण के लिए पिछले दो दिनों से किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर से कूपन के माध्यम से खाद वितरण कराया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस विभाग ने पेयजल की विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मी लगातार लाइन में लगे किसानों तक डिस्पोजल के माध्यम से ठंडा पानी पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी बारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े।

कार्यालय सेनानी 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल
ई-मेल : co7bn_saf@mppolice.gov.in
क्रमांक- 7वीं वाहिनी/विसबल/Qm/1525/2026 दिनांक: 03/08/2026

:: ई-निविदा सूचना ::

वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल के यूनिट चिकित्सालयों (पुरुष चिकित्सालय एवं प्रोतिमा मलिक महिला चिकित्सालय) के इनडोर एवं आऊटडोर के मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाईयां क्रय किये जाने हेतु 03 माह दर अनुबन्ध के तहत खुली ई - निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्तें वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in/ तथा www.mppolice.gov.in पर उपलब्ध हैं, ई-निविदा प्रकाशन उपरांत निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-टेण्डर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा, इस हेतु ई-निविदा पोर्टल पर अद्यतन रहें।

सेनानी
7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल

जी-16730/26 "बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल"

2027 विश्व कप को लेकर अटकलें तेज, मोहम्मद कैफ के बयान से बढ़ी चर्चा, रोहित का चयनकर्ताओं को संदेश

मुझे ड्रॉप करना है तो कर दो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा

नई दिल्ली, एजेंसी

लॉर्ड्स के शतक के बाद फिर सुर्खियों में रोहित, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेली गई 138 रनों की शानदार पारी के बाद उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का एक बयान सामने आया है, जिसने रोहित के भविष्य और 2027 वनडे विश्व कप में उनकी भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कैफ का मानना है कि रोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन के जरिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और चयनकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि वह खुद संन्यास लेने वाले नहीं हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान मोहम्मद कैफ ने कहा कि रोहित शर्मा का रवैया बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। उनके अनुसार रोहित का संदेश यही है कि यदि चयनकर्ताओं को लगता है कि वह टीम के योग्य नहीं हैं तो उन्हें बाहर कर सकते हैं, लेकिन वह स्वयं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला नहीं करेंगे। कैफ ने कहा कि लॉर्ड्स का शतक इस बात का संकेत है कि रोहित अभी भी बड़े मुकाबलों में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं और उनका पूरा ध्यान केवल अच्छा प्रदर्शन करने पर है।

शतक से आलोचकों को दिया जवाब

इंग्लैंड दौरे की शुरुआत में रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा था, जिसके चलते उनकी फॉर्म और भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि चयनकर्ता 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार करने की दिशा में सोच रहे हैं। हालांकि, लॉर्ड्स में शानदार शतक लगाकर रोहित ने साबित कर दिया कि अनुभव और क्लास आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने।

विश्व कप 2027 को लेकर बना हुआ है सस्पेंस

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के भविष्य को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तस्वीर सामने नहीं आई है। टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं ने यह जरूर कहा है कि रोहित को खुलकर खेलने की आजादी दी गई है, लेकिन अब तक किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह 2027 वनडे विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा होंगे या नहीं। यही वजह है कि उनके भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।

टीम प्रबंधन से स्पष्टता की मांग

मोहम्मद कैफ का मानना है कि इस पूरे मामले में टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर रोहित भविष्य की योजनाओं का हिस्सा हैं तो इस पर खुलकर बात होनी चाहिए और यदि नहीं हैं तो भी स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए। फिलहाल रोहित शर्मा अपने बल्ले से जवाब देने में विश्वास रखते हैं और उनका हालिया प्रदर्शन बताता है कि वह अभी भी भारतीय टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाने का दम रखते हैं। ऐसे में 2027 विश्व कप तक उनका सफर जारी रहेगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले समय में चयनकर्ताओं के फैसलों से ही मिलेगा।

एशियन गेम्स 2026 में युवा बल्लेबाज के पास सुनहरा मौका

इतिहास की दहलीज पर वैभव सूर्यवंशी एक शतक से टूट सकते हैं दो विश्व रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। अब उनकी नजर ऐसे रिकॉर्ड पर है, जो पिछले तीन दशक से अटूट बना हुआ है। एशियन गेम्स 2026 में अगर वैभव के बल्ले से शतक निकलता है तो वह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं होगी, बल्कि क्रिकेट इतिहास की रिकॉर्ड बुक में नया अध्याय लिख देगी। महज 15 साल की उम्र में वैभव के पास पुरुष और महिला दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने का मौका है।

डेब्यू मे ही तोड़ चुके हैं बड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ केवल 18 गेंदों में अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया। 15 वर्ष 118 दिन की उम्र में वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस विस्फोटक प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई और अब उनकी निगाहें अगले बड़े मुकाम पर टिकी हैं। जापान के आइची प्रांत में 24 सितंबर से एशियन गेम्स 2026 के टी20 मुकाबले शुरू होंगे। भारतीय टीम में वैभव का चयन हो चुका है और टूर्नामेंट शुरू होने तक उनकी उम्र 15 वर्ष 181 दिन होगी। यही उम्र उन्हें विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा करती है। यदि इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से शतक निकलता है तो वह क्रिकेट जगत के दो सबसे बड़े आयु-आधारित रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

अफरीदी का 30 साल पुराना रिकॉर्ड खतरे में

पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ 16 वर्ष 217 दिन की उम्र में वनडे शतक लगाया था। लगभग 30 वर्षों से यह रिकॉर्ड अटूट बना हुआ है। लेकिन वैभव यदि एशियन गेम्स में शतक बना देते हैं तो वह 15 वर्ष 181 दिन की उम्र में इस उपलब्धि तक पहुंचकर अफरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सिर्फ पुरुष क्रिकेट ही नहीं, बल्कि महिला और पुरुष दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को मिलाकर सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव की पहुंच में है। यह उपलब्धि फिलहाल रवांडा की फेनी उटागुशिमानिंदे के नाम है, जिन्होंने मार्च 2026 में 15 वर्ष 223 दिन की उम्र में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शतक लगाया था। एशियन गेम्स के दौरान वैभव इस उम्र से 42 दिन छोटे होंगे। यानी अगर उनके बल्ले से शतक निकलता है तो वह ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे कम उम्र के शतकवीर बन जाएंगे।

प्रतिभा, आत्मविश्वास और सुनहरा अवसर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में निडरता, आक्रामकता और परिपक्वता का अनोखा मिश्रण देखने को मिला है। इतनी कम उम्र में बड़े मंच पर दबाव झेलने की उनकी क्षमता ने चयनकर्ताओं और क्रिकेट विशेषज्ञों को प्रभावित किया है। एशियन गेम्स जैसे बहु-खेल आयोजन में भारत की ओर से खेलना ही बड़ी उपलब्धि है।

फिटनेस पर बीसीसीआई का बड़ा एक्शन!

एक नियम से गुजरेंगे सभी खिलाड़ी चोटिल सितारों पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली, एजेंसी

टीम इंडिया में लगातार बढ़ती चोटों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (को बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे अहम खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने के बाद अब बोर्ड ने खिलाड़ियों की फिटनेस जांच प्रणाली में व्यापक बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए एक समान फिटनेस मानक लागू होंगे और इन्हें पूरा करने के बाद ही खिलाड़ी चयन के लिए फिट माने जाएंगे।

अब तक खिलाड़ियों की भूमिका, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अलग-अलग फिटनेस मानक अपनाए जा रहे थे। लेकिन इस व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी को देखते हुए बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने सभी खिलाड़ियों के लिए समान फिटनेस पैरामीटर तय कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को ब्रोंको टेस्ट 5 मिनट 15 से 5 मिनट 20 सेकंड के भीतर पूरा करना होगा। इसके अलावा 2 किलोमीटर रन 9 से 10 मिनट में पूरी करनी होगी और यो-यो टेस्ट में न्यूनतम 16.5 अंक हासिल करना अनिवार्य रहेगा। इन मानकों पर खरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ही फिट माना जाएगा।

चोटों से टीम मैनेजमेंट परेशान

हाल के महीनों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ियों की चोट रही है। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं थे। हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी भी फिटनेस समस्याओं के कारण टीम से बाहर रहे। लगातार खिलाड़ियों के बाहर होने से कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए संतुलित प्लेइंग इलेवन चुनना चुनौती बन गया है। फिटनेस व्यवस्था पर सवाल तब और तेज हो गए जब हर्षित राणा को इंग्लैंड दौरे के दौरान चोटिल बताकर वापस भेजा गया, लेकिन बाद में सामने आया कि उन्हें गंभीर चोट नहीं बल्कि केवल क्रैम्प्स थे। इसके अलावा उनका वजन भी तय सीमा से अधिक पाया गया। चयन के समय उनका वजन 97 किलोग्राम था, जबकि बाद में अधिकतम सीमा 96 किलोग्राम तय की गई।

ट्रेंट बोल्ट और पोलार्ड पर गिरी गाज, एमआई केपटाउन ने किया रिलीज... मुंबई इंडियंस भी ले सकती है बड़ा फैसला

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका की टी-20 लीग के अगले सत्र से पहले मौजूदा चैंपियन मुंबई केपटाउन ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। 5 अगस्त को सभी फ्रेंचाइजी ने अपने बनाए रखे और बाहर किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी की। मुंबई केपटाउन ने अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, विस्फोटक हरफनमौला खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वान डर डुसेन को टीम से बाहर कर दिया है। बता दें कि 37 वर्षीय ट्रेंट बोल्ट का पिछला सत्र उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने 10 मुकाबलों में केवल 8 विकेट लिए। इतना ही बोल्ट का प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग में भी निराशाजनक रहा। मुंबई ने उन्हें बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन वह सिर्फ पांच मुकाबले खेल सके और दो विकेट ही हासिल कर पाए। लगातार कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए अब यह माना जा रहा है कि अगली खिलाड़ी नीलामी से पहले मुंबई उन्हें अपनी मुख्य टीम से भी बाहर करने पर विचार कर सकती है।

मनोरंजन **बॉलीवुड का कोना**

लॉकअप-2 में पलटा खेल, श्रेया कालरा बनीं दूसरी फाइनलिस्ट

रियलिटी शो लॉकअप-2 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और फिनाले की जंग रोमांचक होती जा रही है। शिवांगी जोशी के बाद अब कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा ने भी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शो के ताजा एपिसोड में एट-रिस्क कंटेस्टेंट्स आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे और राम कपूर ने श्रेया को दूसरा फाइनलिस्ट चुना। फाइनलिस्ट बनने के बाद श्रेया ने अपने सफर और बाकी प्रतियोगियों की रणनीति को लेकर खुलकर बात की। शिल्पा शिंदे के साथ बातचीत में श्रेया कालरा ने कहा कि कई प्रतियोगियों ने उन्हें लगातार निशाना बनाया, लेकिन यही रणनीति आखिरकार उनके लिए फायदे का सौदा बन गई। उन्होंने कहा कि किसी एक प्रतिभागी को लगातार अलग-थलग करने से दर्शकों की सहानुभूति उसी के साथ जुड़ जाती है और उसका खेल मजबूत हो जाता है। श्रेया का मानना है कि कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी इस बात को समझने में नाकाम रहे।

श्रेया ने खासतौर पर योगेश रावत का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें रियलिटी शो का अनुभव होने के बावजूद हालात का सही आकलन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, ÷राम और वरुण का रियलिटी शो का अनुभव नहीं है, लेकिन योगेश तो दो बड़े शो कर चुके हैं। उन्हें समझना चाहिए था कि किसी एक खिलाड़ी को लगातार घेरने से वही मजबूत बन जाता है। मुझे निशाना बनाते-बनाते उन्होंने मुझे ही फाइनलिस्ट बना दिया।÷

कंटेस्टेंट्स पर साधा निशाना, बोलीं- मुझे खुद ही फिनाले तक पहुंचा दिया

फिनाले की दौड़ हुई दिलचस्प

अब शो अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। फिलहाल घर में शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत बचे हैं। इन पांचों के बीच ट्रॉफी जीतने की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। शो को रितेश और फराह खान होस्ट कर रहे हैं, जबकि छह सप्ताह तक चले इस रियलिटी शो में 14 प्रतिभागियों ने अलग-अलग चुनौतियों का सामना किया। टास्क जीतकर इन-गेम करेंसी हासिल करना और उसी के जरिए अपनी जरूरतें पूरी करना शो का अहम हिस्सा रहा है। श्रेया कालरा एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने वर्ष 2020 में रियलिटी शो रोडीज में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लेकर पहचान बनाई थी।

फरहाना ने रोहित को बताया मजबूत सपोर्ट कहा- खतरनाक स्टंट करने की देते हैं हिम्मत

स्टंट आधारित शो खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट्स को शारीरिक ताकत के साथ-साथ मानसिक मजबूती भी दिखानी पड़ती है। ऐसे में होस्ट की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि उनका हौसला बढ़ाना कई बार कंटेस्टेंट्स को अपने डर पर जीत हासिल करने में मदद करता है। इस कड़ी में अभिनेत्री फरहाना भट्ट ने शो के होस्ट और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोहित खिलाड़ियों में ऐसा आत्मविश्वास भर देते हैं कि वे उन स्टंट को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे वे शुरुआत में डर रहे होते हैं।

बिग बॉस 19 में नजर आ चुकीं फरहाना भट्ट ने आईएएनएस से खास बातचीत में रोहित शेट्टी के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, रोहित एक शानदार होस्ट हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कंटेस्टेंट्स को लगातार प्रेरित करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टंट देखकर आपको डर लगने लगता है और आपको लगता है कि शायद आप उसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी समय रोहित शेट्टी आपके पास खड़े हों और आपका साथ दे रहे हों, तो आपको अलग ही हिम्मत मिलती है।उन्होंने आगे कहा, रोहित के सपोर्ट के साथ कोई भी कंटेस्टेंट मौत के कुएं जैसे डरावने स्टंट में भी उतरने का साहस जुटा सकता है। शो को लेकर फरहाना ने कहा, इस शो में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और सौ फीसदी समर्पण की जरूरत होती है। फरहाना ने कहा, मेरा मानना है कि इस शो में वही आगे बढ़ सकता है, जो हर स्टंट में अपना सौ फीसदी देता है। जब आप बिना डरे पूरी मेहनत के साथ चुनौती का सामना करते हैं, तभी आपका असली प्रदर्शन सामने आता है। दर्शक भी उसी

मेट्रो बाजार

एआई विकासशील देशों के लिए बन रहा लाइफलाइन

नई दिल्ली । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विकासशील देशों के लिए लाइफलाइन का काम कर रहा है। इससे वे एक दशक में वह हासिल कर सकते हैं जो इसके बिना एक सदी में हासिल हो सकता था, लेकिन यह तभी संभव है जब इन देशों की सरकारें शक्ति, संपर्क, कौशल और संस्थागत गुणवत्ता में मौजूद कमियों को तेजी से दूर करें। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम और मध्यम आय वाले देशों की तुलना में, ज्यादा आय वाले देशों में नौकरियों के जेनरेटिव एआई की वजह से ऑटोमेशन के दायरे में आने का खतरा तीन गुना से अधिक है। कम और मध्यम आय वाले देशों में मौजूदा नौकरियों में से 4.5 प्रतिशत पर ऑटोमेशन का खतरा है, जबकि अधिक आय वाले देशों में यह आंकड़ा 14.2 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 16.2 प्रतिशत नौकरियों की प्रोडक्टिविटी में एआई से काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा ज्यादा आय वाले देशों के लिए अनुमानित 18.7 प्रतिशत के करीब है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल ने कहा, ÷एआई ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक नई उम्मीद दी है, और उन्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके फायदों के लिए उन्हें बड़े मॉडल या बड़े डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, छोटे और सस्ते एआई टूल्स को स्थानीय हालात के हिसाब से ढालकर, वे लाखों लोगों तक बेहतर मेडिकल केयर, शिक्षा, न्यायिक सेवाएं और खेती से जुड़ी मदद पहुंचा सकते हैं।

पुरानी कारों को ऑटो एलपीजी में बदलने के लिए राष्ट्रीय रेट्रोफिट नीति जरूरी: इंडस्ट्री

नई दिल्ली । भारत का तेजी से बढ़ता सेकेंड-हैंड कार बाजार शहरी प्रदूषण कम करने का एक तेज और व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। इसी को देखते हुए सरकार को इस्तेमाल में मौजूद पेट्रोल और डीजल वाहनों को ऑटो एलपीजी में बदलने के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय रेट्रोफिट नीति लागू करनी चाहिए। यह मांग बुधवार को इंडस्ट्री की ओर से की गई। भारत में ऑटो एलपीजी को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था आईएसी ने कहा कि देश में हर साल सेकेंड-हैंड कारों की बिक्री करीब 60 लाख के स्तर पर पहुंच रही है, ऐसे में एक समर्पित रेट्रोफिट नीति की तत्काल जरूरत है।

उद्योग संगठन के अनुसार, ऐसी नीति देश के तेजी से बढ़ते प्री-ओन्ड वाहन बाजार को वाहन प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी माध्यम बना सकती है। खासकर दिल्ली एनसीआर और अन्य प्रदूषण प्रभावित शहरों में इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

रिपोर्ट में उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेकेंड-हैंड वाहनों का कारोबार नई कारों की बिक्री की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में लगभग 46 लाख सेकेंड-हैंड वाहनों के लेन-देन का आंकड़ा 2030 तक 1 करोड़ से अधिक पहुंच सकता है। इस दौरान इसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) 12-13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हर नई कार की बिक्री पर एक से अधिक पुरानी गाड़ी का स्वामित्व बदलता है। यदि भारतीय सड़कों पर चल रहे करोड़ों पेट्रोल और डीजल वाहनों में से केवल एक हिस्से को भी ऑटो एलपीजी में बदला जाए, तो वायु प्रदूषण में बड़ी कमी लाई जा सकती है। विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर और अन्य प्रदूषण प्रभावित शहरों में इसका बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

मणिपुर की जीवनरेखा लोकटक झील पर संकट, घटता जलस्तर और बढ़ता प्रदूषण बना चिंता

इंफाल। मणिपुर की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकटक झील इन दिनों पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की यह झील न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। झील में पाए जाने वाले तैरते द्वीप, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'फुमदी' कहा जाता है, इसकी विशेष पहचान हैं। हाल के वर्षों में जलस्तर में बदलाव, बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण झील का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो जैव विविधता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

'मातृभाषा न जानना गर्व नहीं, अपमान है', छात्रों से बोले अभिनेता धनुष

चेन्नई. एजेंसी

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता धनुष ने मातृभाषा के

महत्व पर जोर देते हुए छात्रों से तमिल पढ़ने और लिखने की अपील की है। चेन्नई के थाई सत्या मैट्रिकुलेशन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा न जानना गर्व की नहीं, बल्कि अपमान की बात है।

धनुष ने बेल्जियम में फिल्म शूटिंग के दौरान का अनुभव साझा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी भाषाएं सीखना अच्छी बात है, लेकिन वह केवल अतिरिक्त ज्ञान हैं। छात्रों और शिक्षकों को तमिल में संबोधित करते हुए अभिनेता ने बताया कि स्कूल के दिनों में वह अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं बोल पाते थे, लेकिन तमिल पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने छात्रों से अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने का आग्रह किया।

60 से 62 साल करने के प्रस्ताव पर दो हफ्ते में जवाब-तलब

जजों के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त राज्यों से पूछा- आखिर क्यों नहीं बढ़ रही उम्र

नई दिल्ली. एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मुद्दे पर राज्यों के रुख पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दो सप्ताह के भीतर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ और सरकारी कर्मचारियों की अलग सेवानिवृत्ति आयु जैसे तर्क इस फैसले में बाधा नहीं बन सकते।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायिक अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने और बाद में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अधिक खर्चीली हो सकती है। अनुभवी न्यायाधीशों को सेवा में बनाए रखना न्याय व्यवस्था के लिए लाभकारी है। पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी सामान्य सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनकी नियुक्ति भले ही राज्य सरकारों के माध्यम से होती हो, लेकिन वे एक स्वतंत्र और विशिष्ट वर्ग का हिस्सा हैं। इसलिए उनकी तुलना अन्य सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस विषय पर स्वतंत्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए दो सप्ताह के भीतर निर्णय लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई राज्य सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका लाभ उन न्यायिक अधिकारियों को भी दिया जाना चाहिए, जो इस दौरान सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

राज्यों के तर्कों को किया खारिज

सुनवाई के दौरान कई राज्य सरकारों ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध किया। राज्यों का कहना था कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और न्यायिक अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में अंतर पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि अनुभवी न्यायाधीशों को बनाए रखना नए अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की तुलना में अधिक व्यावहारिक हो सकता है। अदालत ने कहा कि केवल वित्तीय कारणों का हवाला देकर न्यायिक सुधारों को नहीं रोका जा सकता। राज्यों को इस मुद्दे पर व्यापक और दूरगामी सोच के साथ फैसला लेना चाहिए।

'जज सरकारी कर्मचारी नहीं, अलग वर्ग'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी सामान्य सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते। अदालत ने कहा कि उनकी नियुक्ति भले ही राज्य सरकारों के माध्यम से होती हो, लेकिन वे न्यायपालिका के स्वतंत्र ढांचे का हिस्सा हैं। इसलिए उनकी सेवा शर्तों की तुलना अन्य सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायिक अधिकारियों को एक अलग और विशिष्ट वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी भविष्य में न्यायपालिका से जुड़े कई प्रशासनिक फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुंगेर में ईडी का बड़ा एक्शन

करोड़ों के फर्जीवाड़े में जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर के घर छापामारी

जमालपुर/मुंगेर. एजेंसी

जमालपुर थाना क्षेत्र के नया टोला फूलका स्थित जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास पर आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापेमारी की। आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम गुरुवार की सुबह तड़के ही पहुंच गई और स्थानीय लोगों के जागने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी।

टीम ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की।सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम मामले के प्राथमिक आरोपित जयधन तांती और प्रिया राजीव रंजन से भी पूछताछ कर रही है। वित्तीय लेनदेन, निवेश से जुड़े कागजात और अन्य साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। बताया जाता है कि जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाकर फरार होने का आरोप है। 18 नवंबर 2024 को कंपनी के कार्यालय में ताला लगने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने जमालपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कांड संख्या 224/24 दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि कंपनी चिटफंड की तर्ज पर निवेश कराकर लोगों की बड़ी रकम लेकर फरार हो गई। पुलिस जांच के दौरान कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव फरार हो गए थे। बाद में उन्होंने मुंगेर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था और तब से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। अब ईडी धन शोधन और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के पहलुओं की जांच कर रही है।

पीओके चुनाव में नवाज की धमाकेदार वापसी

विरोध और बहिष्कार के बीच पीएमएल-एन को प्रचंड बढ़त

34 में से 24 सीटों पर जीत के साथ सरकार गठन तय

इस्लामाबाद. एजेंसी

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक घोषित 34 सीटों में से पार्टी 24 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जिससे उसकी सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। करीब दस साल बाद पीओके की सत्ता में पीएमएल-एन की वापसी होती दिखाई दे रही है।

सुरक्षा कारणों और भारी मानसूनी बारिश को देखते हुए चुनाव तीन चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले दो चरणों का मतदान और मतगणना पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 11 सीटों पर 10 अगस्त को मतदान होगा। क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में 50 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। चुनाव से पहले प्रतिबंधित संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) ने मतदान के बहिष्कार की अपील की थी। संगठन के समर्थकों और पुलिस के बीच कई स्थानों पर झड़पें भी हुईं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव के दौरान 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद भी गहराया रहा। जेएएसी का आरोप है कि इन सीटों के कारण पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव मिलता है। हालांकि, पीओके की सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने की बात कही है। नतीजों के बाद नवाज शरीफ ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।

तीन चरणों में चुनाव

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता राजा शकील के अनुसार, सुरक्षा चुनौतियों और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मतदान को अलग-अलग चरणों में आयोजित किया गया। पहले दो चरणों में 34 सीटों पर मतदान और मतगणना पूरी हो चुकी है। अब शेष 11 सीटों के लिए 10 अगस्त को मतदान होगा। मुजफ्फराबाद सहित कई क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत 50 से 56 प्रतिशत के बीच रहा। विरोध और बहिष्कार की अपील के बावजूद मतदाताओं की बड़ी भागीदारी ने चुनाव प्रक्रिया को मजबूती दी है। अधिकारियों का दावा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया।

झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान समेत 2 की मौत

झांसी. एजेंसी

झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूंछ थाना क्षेत्र के पास हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में उसके एक अन्य साथी की भी जान चली गई, जबकि 3 अन्य युवक गम्भीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने आया था। मुलाकात के बाद लौटते समय पूंछ क्षेत्र के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही

स्थानीय पुलिस और ऐम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोठ भेजा गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद अबान अहमद को मृत घोषित कर दिया। हादसे में उसके एक अन्य साथी की भी मौत हो गई। 3 घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गम्भीर स्थिति को देखते हुए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलिज रिफर कर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और दुर्घटनास्थल पर पहुंचे तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया हादसा तेज गति और वाहन के नियन्त्रण खोने के कारण हुआ प्रतीत होता है। अबान अहमद, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। उसके बड़े भाई अली अहमद इस समय झांसी जेल में निरुद्ध हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल और पुलिस अधिकारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई।

ग्रेटर नोएडा में दूषित जल पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार

ग्रेटर नोएडा. एजेंसी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला ग्रीन आर्क सोसायटी में दूषित गंगाजल की आपूर्ति से 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। निवासियों का दावा है कि जांच में पानी में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। जिसके बाद सोसायटी के 11 टावरों में रहने वाले 1640 परिवारों में दहशत है। लोगों ने एओए और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सोसायटी के लोगों का कहना है कि पिछले दो महीने से गंगाजल की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। बीते एक सप्ताह में सोसायटी के वॉट्सएप ग्रुपों पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार के केस लगातार सामने आने लगे। वहीं, स्थिति बिगड़ने पर एओए ने पानी के नमूने निजी लैब में भिजवाए। रिपोर्ट में पानी को पीने योग्य नहीं पाया गया। इसमें कोलीफार्म और ई.कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी मिली, जो जलजनित बीमारियों का मुख्य कारण माने जाते हैं। लोगों का दावा है कि सिर्फ दो सप्ताह में 100 से अधिक लोग बीमार हुए हैं।

मेट्रो एंकर

अयोध्या : राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था हुई और आसान

बुजुर्ग श्रद्धालुओं को आधार दिखाने पर मिलेगा सुगम दर्शन पास

अयोध्या. एजेंसी

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन के लिए नई सुविधाओं की घोषणा करते हुए वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। अब 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन पास के लिए किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वे केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर आसानी से भागवान के दर्शन पास प्राप्त कर सकेंगे।

इसके साथ ही ट्रस्ट ने राम दरबार दर्शन के लिए लागू विशेष पास व्यवस्था भी पूरी तरह समाप्त कर दी है। अब श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के बाद प्रथम तल स्थित राम दरबार के दर्शन के लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य दर्शन कतार से गुजरने के बाद श्रद्धालु सीधे राम दरबार पहुंच सकेंगे। अब तक राम दरबार के दर्शन सीमित संख्या में जारी किए जाने वाले विशेष पास के माध्यम से कराए जाते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दर्शन प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम हो गई है। सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने के बीच ट्रस्ट के इस फैसले को भक्तों के लिए

बड़ी राहत माना जा रहा है। श्रद्धालुओं ने भी इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। मेरठ से आईं निधि ने बताया कि इस बार बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के रामलला और राम दरबार दोनों के दर्शन आसानी से हो गए। वहीं, ग्वालियर के राकेश शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था से हजारों श्रद्धालुओं का समय और परेशानी दोनों कम होंगी।

राम दरबार के लिए खत्म हुई वीआईपी पास व्यवस्था

राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रथम तल स्थित राम दरबार के दर्शन के लिए लागू विशेष पास व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। पहले श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में जारी होने वाले अलग पास के जरिए ही राम दरबार के दर्शन की अनुमति मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत अब श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बाद सीधे राम दरबार पहुंच सकेंगे। इससे दर्शन प्रक्रिया सरल होने के साथ समय की भी बचत होगी। मेरठ और ग्वालियर से आए श्रद्धालुओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहले जानकारी के अभाव में कई लोग राम दरबार के दर्शन से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब एक ही कतार से दोनों स्थानों के दर्शन संभव हो गए हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564